नई दिल्ली
मंगलवार
03 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 60
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



मुख्यमंत्री ने गडकरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय....पेज-05

DELHIN/2014/58158

दीपोत्सव में श्रद्धालुओं को न हो परेशानी, व्यवस्थाएं...पेज-08

एक नजर

सोनिया गांधी ने लालू यादव से की मुलाकात

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल की पुरानी यादें ताजा कीं और मनरेगा, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) जैसे कानूनों के लागू होने से जुड़े अनुभव साझा किए। सोनिया ने लालू से उनकी बेटी एवं सांसद मीसा भारती के आवास पर मुलाकात की। लालू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि सोनिया गांधी उनके आवास पर पहुंचीं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुईं।

लालू ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी एवं जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा, आरटीई और आरटीआई जैसे कानूनों के माध्यम से देशवासियों को सशक्त बनाया गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दिए जाने का भी उल्लेख किया। इस मुलाकात पर तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के दो अनुभवी नेताओं की यह मुलाकात पारिवारिक और आत्मीय रही। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के सुख-दुख में मजबूती से साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए की विकास गाथा से जुड़े दोनों नेताओं के संघर्ष, संस्मरण, चिंतन और उपलब्धियों को सुनना तथा उनसे सीखना उनके लिए सौभाग्य की बात है। ऐसी मुलाकातों से प्रेरणा मिलती है कि दृढ़ संकल्प और सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण की पांबदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 324 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। आयोग की ग्रैप उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा आईआईटीएम द्वारा जारी पूर्वानुमानों की समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है और आने वाले दिनों में भी एक्यूआई के बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण बताया गया है। इसके साथ ही ग्रैप के पहले चरण के सभी उपाय भी पहले की तरह जारी रहेंगे। आयोग के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 31 अक्टूबर को 117 यानी मध्यम श्रेणी में था। इसके बाद 1 नवंबर को यह बढ़कर 261 यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। वहीं 2 नवंबर को एक्यूआई में और वृद्धि दर्ज की गई और यह 324 हो गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। ग्रैप-2 के तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। ग्रैप दो लागू होने के बाद संबंधित एजेंसियों को प्रमुख सड़कों पर रोजाना मैकेनिकल और वैक्यूम स्वीपिंग के साथ पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से रात और सुबह के समय सफाई अभियान तेज करने को कहा गया है।

अगले दस वर्षों में 500 गीगावॉट नयी गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता जोड़ेगा भारतः मोदी

पीएम मोदी ने भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कहा

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत अगले 10-11 वर्षों में 500 गीगावाट अतिरिक्त गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने का प्रयास करेगा। इससे इस दशक के अंत तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश अवसर पैदा होंगे। मोदी ने भारत मंडपम में भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत में राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मांग और विकास की संभावनाएं हैं, जो इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की है और देश करीब 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर चुका है। भारत सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।



प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2021 के सम्मेलन में 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया था। पेरिस समझौते के तहत कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य भी भारत ने 2025 में ही हासिल कर लिया, जो निर्धारित समय से पांच साल पहले है। मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी और पश्चिम एशिया संकट सहित पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई बड़े आर्थिक संकटों का सामना किया है। पश्चिम एशिया का संकट अभी भी जारी है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया है और देश की विकास दर ऊंची बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने पिछले एक दशक में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश नहीं किया होता और इसके लिए नई व्यवस्थाएं विकसित नहीं की होतीं, तो इन वैश्विक संकटों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहीं अधिक गंभीर हो सकता था। इन संकटों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा सीधे आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का आधार स्वच्छ ऊर्जा ही है। मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वादों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2021 में भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 10-11 वर्षों में 500 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर सरकारी भवन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़क प्रकाश व्यवस्था को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। देश में 44 हजार से अधिक सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है, जिससे हर साल करीब 700 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य है। पिछले 24-25 महीनों में 65 लाख से अधिक घर इस अभियान से जुड़ चुके हैं। मोदी ने किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत 30 लाख से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अनुमान है कि सौर पंपों का इस्तेमाल करने वाला प्रत्येक किसान सालाना करीब एक लाख रुपये की बचत कर सकता है। किसानों को अपनी खाली जमीन और खेतों की मेड़ों पर सौर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक गांवों में यह व्यवस्था लागू हो सके। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार पर जोर देते हुए स्टार्टअप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), शोधकर्ताओं और उद्यमियों से ऐसे मॉडल विकसित करने का आह्वान किया, जिनसे परिवारों की अधिकतम ऊर्जा जरूरतें पूरे वर्ष और चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से पूरी हो सकें।

झुंझुनूं में करंट लगने से सड़क निर्माण में लगे आठ मजदूरों की मौत, हाईटेंशन लाइन से टकराई मशीन

झुंझुनू,एजेंसी। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में सोमवार को सड़क बना रहे आठ मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। पांच लोग झुलस गए। उनका उदयपुरवाटी सीएचसी में इलाज चल रहा है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनो को 2-2 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में श्रमिकों की असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उदयपुरवाटी थानाधिकारी रामपाल ने बताया कि हादसा छापोली-कदंब कुंड मार्ग पर सीकर-नीमकाथाना स्टेट हाईवे से करीब 150 मीटर दूर हुआ। रोड़ी-बजरी मिलाने के काम में आने वाली एक मशीन ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। इससे उसमें करंट दौड़ गया। वहां काम कर रहे मजदूर करंट की चपेट में आ गए। हाईवोल्टेज लाइन का तार रोड़ी-बजरी (कंक्रीट) मिक्सर मशीन के हाइड्रोलिक जैक से टच हुआ था। घटना के बाद ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। हादसे में हालेड़ा मंडावरा निवासी हरिराम गुर्जर (30) पुत्र शंकर लाल, मंगलचंद (22) पुत्र गिरधारीलाल गुर्जर, कालूराम गुर्जर (29) पुत्र भीखाराम गुर्जर और पवन गुर्जर (23) पुत्र जगदीश गुर्जर की मौत हो गई। ये चारों एक परिवार के थे। इसके अलावा छापोली निवासी विष्णु सैनी (38) पुत्र नानूराम सैनी, सुरेंद्र उर्फ सुरेश सैनी (30) पुत्र महावीर सैनी, मुकेश सैनी (27) पुत्र शंकरलाल सैनी और फतेहचंद सैनी (32) पुत्र जगदीश की भी करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी। हादसे में छापोली निवासी महेंद्र पुत्र बनवारी लाल सैनी, गीता देवी (45) पत्नी मदन लाल मेघवाल, संतरा देवी (35) पत्नी सतीश मेघवाल, गिदाराम (45) पुत्र धन्नाराम सैनी और मंजू देवी (38) पत्नी राजेश कुमार घायल (झुलसे) हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही है। पोल और बिजली लाइन पेड़ के टच हो रहे हैं। लाइन काटने के लिए फोन किया तो ग्रिड सबस्टेशन (जीएसएस) पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। घायल गिदाराम सैनी ने कहा कि छापोली में हम सभी मशीन को धक्का देकर दूसरी जगह लगा रहे थे, इसी दौरान वह तार के टच हो गई और करंट लग गया। मौके पर 12-13 लोग थे। ग्रामीण घटनास्थल पर कलेक्टर को बुलाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत करवाया। हादसे की जानकारी मिलने पर झुंझुनूं कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग, एसपी कावेंद्र सिह सागर, विधायक भगवानाराम सैनी सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा भी मौके पर पहुंचे। लोगों से घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में श्रमिकों की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार, प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने और घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

आत्मपरिवर्तन राष्ट्र निर्माण की आधारशिलाः जेपी नड्डा

नई दिल्ली,एजेंसी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में यहां के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी महोत्सव के तीसरे दिन आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों की अनूठी छटा देखने को मिली। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आत्मपरिवर्तन को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।



देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने गायत्री मंत्र को नैतिक पतन के विरुद्ध सुरक्षा कवच बताते हुए आंतरिक परिष्कार से युग परिवर्तन का आह्वान किया। समारोह का शुभारंभ देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं की मनोहारी समूह नृत्य प्रस्तुतियों से हुआ। छात्राओं ने 'अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है' भक्ति गीत और 'लागी रे लगन ओ मां की' प्रज्ञागीत पर भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरुदेव एवं माताजी के आदर्शों और युग निर्माण की चेतना को जीवंत किया गया। समारोह के दूसरे सत्र में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य की तप-साधना, करुणा और लोकमंगल के प्रति समर्पण तथा वंदनीया माताजी का त्यागपूर्ण मातृत्व संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने व्यक्ति के आत्मपरिष्कार, परिवार में श्रेष्ठ संस्कारों के संवर्धन तथा अपनी सामर्थ्य और संसाधनों को समाज एवं राष्ट्र के कल्याण में समर्पित करने के तीन प्रमुख संकल्पों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि साधना केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी प्रकट होनी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने दिवाली से ठीक पहले राजधानी के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सचिव-सह-आयुक्त (श्रम) कार्यालय ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी कर सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) को 2025-26 के लिए स्टैच्यूटरी बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

श्रम विभाग के अतिरिक्त श्रम आयुक्त यूके सिन्हा द्वारा जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जो बोनस के हकदार हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में वेज कोड, 2019 लागू हो चुका है और पुराना बोनस एक्ट 1965 खत्म हो गया है। नए नियम के तहत जिन कर्मचारियों का वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह तक है और जिन्होंने कम से कम 30 दिन काम किया है।

दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में दो दिन जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट की सशर्त अनुमति

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगा बैन दिवाली पर दो दिनों के लिए सशर्त हटाने आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के दौरान जला सकेंगे। इस साल दिवाली 8 नवंबर को है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि उपरोक्त अवधि के दौरान भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, ओल्ड-एज होम, शैक्षणिक संस्थान और किसी भी नोटिफाइड साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं जलाया जाएगा। नौ नवंबर से पटाखों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के सभी निर्माताओं और व्यापारियों से एक वित्तीय सुरक्षा लिया जाए। यदि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता है, तो उनकी यह सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय ने साफ किया है कि यह छूट केवल प्रदूषण मुक्त ग्रीन पटाखों के लिए है, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लोग त्योहार मना सकें।



इससे पहले 29 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार करते हुए इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अदालत त्योहारों पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए वह एक संतुलित आदेश पारित करेगी, जिसमें पटाखों के प्रकार और उन्हें जलाने की समय-सीमा तय की जा सकती है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब तक नियमों के धरातल पर ठीक से लागू नहीं किया जाता तब तक हर साल सिर्फ आदेश जारी करना महज मजाक या अकेडेमिक एक्सरसाइज बनकर रह जाता है। न्यायालय ने कहा था कि वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए अफसरों को हाई लेवल और कुछ नये ढंग से सोचना होगा। चूंकि, व्यापारी मांग और आपूर्ति के हिसाब से अवैध रूप से भी पटाखे बेचते हैं, इसलिए सिर्फ पटाखे बेचने पर रोक लगाने से काम नहीं चलेगा।

नौसेना के लिए बनाए जाएंगे अगली पीढ़ी के आठ कॉर्वेट, 53.86 करोड़ रुपये का अनुबंध

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के आठ कॉर्वेट खरीदे जाएंगे, जिनके लिए सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने 53,866.50 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में यह अनुबंध गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ किया गया है। इनमें से पांच कॉर्वेट जीआरएसई बनाएगा, जबकि बाकी तीन कॉर्वेट का निर्माण जीएसएल करेगा।



रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह प्रोजेक्ट भारत की स्वदेशी वॉरशिप डिजाइन और कंस्ट्रक्शन क्षमताओं में एक अहम मील का पत्थर है। यह पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना खुद स्वदेशी रूप से डिजाइन करेगी और एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाएंगे। इन कॉर्वेट में एडवांस्ड मिसाइल, हथियार और सेंसर सूट जैसी आधुनिक क्षमताएं होंगी, जिससे वे हवा, सरफेस और सब-सरफेस डोमेन में मिशन कर सकेंगी। इन जहाजों के समुद्री बेड़े में शामिल होने के बाद नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी, जैसे समुद्री ट्रेड रूट्स की सुरक्षा, एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन करना, कोस्टल डिफेंस को मज़बूत करना, लिटोरल कॉम्बैट ऑपरेशन करना और समुद्री प्रेजेंस और सर्विलांस मिशन करना। यह प्रोजेक्ट डीपीएसयू, प्राइवेट शिपयार्ड और लघु उद्योगों सहित भारतीय औद्योगिक भागीदार के बीच सहयोग मजबूत करके स्वदेशी शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम को काफ़ी बढ़ावा देगा। इन जहाजों के निर्माण से अगले दस सालों में शिपयार्ड में लगभग 72 लाख रोजगार दिवस और लघु उद्योगों में 460 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत में

बिहार संग्रहालय एशिया में प्रथम और विश्व में नौवें स्थान पर

डॉ बीरबल झा ने कहा- बिहार की सांस्कृतिक विरासत को मिली वैश्विक पहचान

नई दिल्ली/पटना। बिहार के लिए गौरव का एक नया अध्याय जुड़ गया है। पटना स्थित बिहार संग्रहालय को वर्थ अ जर्नी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड्स 100 बेस्ट म्यूजियम्स 2026 की सूची में एशिया में पहला और विश्व में नौवाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि से बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।



इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर ब्रिटिश लिंगुआ के प्रबंध निदेशक, शिक्षाविद् एवं लेखक डॉ. बीरबल झा ने बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ प्रमोद कुमार, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह (आईएएस, सेवानिवृत्त) तथा संग्रहालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है। डॉ झा ने कहा कि बिहार संग्रहालय का एशिया में शीर्ष स्थान और विश्व में नौवाँ स्थान प्राप्त करना केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव का अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यह उपलब्धि बताती है कि दूरदर्शी सोच, संस्थागत प्रतिबद्धता और पेशेवर प्रबंधन के बल पर बिहार की संस्थाएँ भी विश्वस्तरीय पहचान बना सकती हैं। उन्होंने कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभागीय नेतृत्व और प्रोत्साहन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बिहार संग्रहालय को मिली यह वैश्विक पहचान राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित करने के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मंत्री के मार्गदर्शन में बिहार की अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं, संग्रहालयों और धरोहर स्थलों को भी नई ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी। डॉ झा ने बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने में दूरदर्शी नेतृत्व, समर्पित टीम और निरंतर संस्थागत प्रयासों की निर्णायक भूमिका होती है। बिहार संग्रहालय की यह उपलब्धि इन्हीं सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्रों, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, मौर्यकालीन इतिहास तथा कला और स्थापत्य की समृद्ध परंपरा से संपन्न बिहार की सांस्कृतिक विरासत पूरी मानवता की साझा धरोहर है। बिहार संग्रहालय इस विरासत को आधुनिक प्रस्तुति, सुव्यवस्थित दीर्घाओं और उत्कृष्ट संग्रहों के माध्यम से देश-दुनिया के सामने रख रहा है।

राजधानी में विकास और जनकल्याण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम : रेखा गुप्ता

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फरवरी 2025 से दिल्ली में विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों का सिलसिला जारी है। इन बदलावों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सोमवार को चाणक्यपुरी में आयोजित मीडिया संवाद व दिवाली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनसरोकारों के प्रति मीडिया की सजगता और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनका योगदान अभिनंदनीय है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से संवाद भी किया और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी।



इस मौके केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज कुमार सिंह, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज सिंह, विधायक अनिल कुमार शर्मा, हरीश खुराना सहित भाजपा के पदाधिकारी और मीडिया जगत के साथी उपस्थित रहे। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिवाली मंगल मिलन में पत्रकार साथियों के साथ हंसी-खुशी के माहौल में दीपावली की खुशियां साझा कीं। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने भी मीडिया जगत के साथियों से दिल्ली के विकास व जनहित के मुद्दों पर खुलकर, आत्मीय व सकारात्मक चर्चा की और सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दीपावली सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा लेकर आए।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज मीडिया जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रकाश, उल्लास एवं उत्साह का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ मीडिया जगत के वरिष्ठ साथियों से आत्मीय भेंट हुई। इस संवाद ने सरकार और मीडिया के बीच समन्वय और विश्वास को और मजबूत किया है। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज ने भी दीपावली की शुभकाएनाएं देते हुए कहा कि यह दीपोत्सव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे।

दिल्ली में पुलिसकर्मियों ने वकीलों के साथ विवाद में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के जवानों ने सोमवार को शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ झड़प के बाद एसीपी मानस्वी वशिष्ठ और एसएचओ अरुण कुमार के तबादलों के विरोध में मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एसीपी मानस्वी वशिष्ठ ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने सीपी के सामने अपनी मांग रखी। हालांकि अपेक्षा से बहुत कम लोगों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिला। हमने अपनी मांगें उन्हें बता दी हैं और उन पर चर्चा चल रही है। इससे पहले पुलिस अधिकारी तीन घंटे से अधिक समय तक कमिश्नर से मुलाकात की मांग को लेकर बाहर जमा रहे। मामला 23 अक्टूबर को शाहदरा इलाके का है। यहां एक विवाद से जुड़ी झड़प में वकील ललित बंसल को पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर सिर में गंभीर चोट आई थीं। शाहदरा पुलिस स्टेशन में इसपर एफआईआर दर्ज की गई। उसी शाम कई वकील कार्रवाई की मांग करते हुए थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि एसीपी वशिष्ठ और एसएचओ अरुण कुमार ने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वकीलों का कहना है कि उन्हें अगले दिन पता चला कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और कथित तौर पर रिहा कर दिया गया। वे मामले को संभालने के तरीके का विरोध करने के लिए थाने लौटे और झड़प हुई। वकीलों ने आरोप लगाया कि एसीपी ने रिवॉल्वर दिखाकर उन्हें धमकाया। वहीं पुलिस ने आरोप लगाया कि वकीलों ने दुर्व्यवहार किया, कामकाज में बाधा डाली और एक वकील ने एसएचओ को खींचने की कोशिश की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एसीपी वशिष्ठ की शिकायत के आधार पर 15-20 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों के बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने आपातकालीन बैठक की और एसीपी, एसएचओ और अन्य अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित करने की मांग करते हुए एक परिपत्र जारी किया। दिल्ली भर के जिला न्यायालयों के वकीलों ने काम बंद कर दिया। इसके बाद 28 अक्टूबर को एसीपी मानस्वी वशिष्ठ का तबादला एसडीपीओ गांधी नगर (शाहदरा) से महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) में कर दिया गया। वहीं एसएचओ अरुण कुमार का तबादला शाहदरा पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस सुरक्षा शाखा में कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों, दिल्ली बार काउंसिल के प्रतिनिधियों और बार एसोसिएशन के नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। इसके बाद आज लगभग 80-100 दिल्ली पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर एर के बाहर तीन घंटे से अधिक समय तक इकट्ठा रहे। वे तख्तियां लिए खड़े थे।

हाई कोर्ट का दिल्ली में बाहरी वाहनों के प्रतिबंध पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें विंटर एक्शन प्लान के तहत एक नवंबर से 31 जनवरी, 2027 तक राजधानी में उन वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी, जो दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं और प्री-बीएस-VI एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि मामले को 27 नवंबर को संबंधित मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए। यह याचिका फरीदाबाद निवासी एक वकील गुरमुख दास कोहली ने दायर की है। इसमें पर्यावरण और वन विभाग की 23 जून की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें तीन महीने की अवधि के लिए दिल्ली के बाहर पंजीकृत प्री-बीएस-VI वाहनों पर राजधानी में एंट्री की अनुमति नहीं है। याचिका में इस प्रतिबंध को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में पंजीकृत बीएस-VI से पहले के वाहनों को प्रतिबंध अवधि के दौरान राजधानी में चलने की अनुमति जारी रहेगी, जबकि पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत समान वाहनों को प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि वर्गीकरण वाहन के उत्सर्जन विशेषताओं के बजाय पंजीकरण के स्थान पर आधारित है।

दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा बंगला साहिब से रकाबगंज साहिब तक निकाली श्रद्धांजलि पदयात्रा

नई दिल्ली,एजेंसी। वर्ष 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार में मारे गए निर्दोष लोगों की स्मृति में सोमवार को दिल्ली में श्रद्धांजलि पदयात्रा निकाली गई। '1984-कांग्रेस द्वारा सिखों का नरसंहार नहीं भूलेगा हिन्दुस्तान' के नारे के साथ 1984 के पीड़ित परिवारों के सदस्यों, सिख संगत और दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक गुरुवाणी का जाप करते हुए पदयात्रा की। पदयात्रा के समापन पर नरसंहार में शहीद हुए सिखों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।



दिल्ली भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद बांसुरी स्वराज और वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव बब्बर भी पदयात्रा में शामिल हुए। उनके साथ 1984 के पीड़ित परिवारों के सदस्य सरदार करतार सिंह, प्रीति सिंह कौर, जसवीर कौर, भागी कौर, परमजीत कौर और मनप्रीत कौर सहित सैकड़ों सिख महिलाएं, निहंग जत्थेदार, तिलक विहार निवासी प्रभावित परिवारों के सदस्य और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदयात्रा की व्यवस्था भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संभाली। इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय के लोगों को संगठित तरीके से निशाना बनाया गया। एक-एक घर की पहचान कर सिख परिवारों को बाहर निकाला गया और उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आम जनता का काम नहीं था, बल्कि कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थित एवं संरक्षित लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। सहरावत ने कहा कि कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर एक नवंबर के संदर्भ में राजनीति किए जाने से सिख समाज के पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज हमेशा देश और समाज के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अन्याय और अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि वे देश में अराजकता फैलाने और सिख समाज के जख्मों को कुरेदने का प्रयास न करें।

उपराज्यपाल ने नरेला में डीडीए के विकास कार्यों का लिया जायजा



नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार नरेला का दौरा करके दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा किए जा रहे प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने डीडीए के 'रेडी-टू-मूव' (रहने के लिए तैयार) फ्लैटों का निरीक्षण किया, जो दिल्ली में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प को दोहराता है। इसके अलावा, सेक्टर जी7/जी8 में राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित भूमि (एक एकीकृत शिक्षा केंद्र के लिए) और 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' के तहत पहले सेक्टर—सेक्टर 8क्र(जोन क्र-ढ्ढ)—की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये पहल एक नियोजित और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देंगी और विकसित दिल्ली के निर्माण में नरेला की भूमिका को और मजबूत करेंगी।

जेएनयू प्रोफेसर अकोइजाम की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजाम को राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच में सुनवाई के दौरान अकोइजाम ने न्यायालय को बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत दिए जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले में जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2027 में होगी। अकोइजाम जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स' से जुड़े हुए थे। कई छात्राओं की शिकायतों के बाद जेएनयू की इंटरनल कमेटी ने इस मामले की जांच की। जांच के नतीजों के आधार पर कमेटी ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने 9 अक्टूबर को अकोइजाम को बर्खास्त कर दिया। अकोइजम ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार करके इस पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रेरित और इसमें प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है। आज अकोइजाम की ओर से वकील मोइरांगथेम गुनेधोर सिंह ने तर्क पेश किया।

निगम के दिवंगत कर्मचारियों के 46 आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पत्र

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने सोमवार को निगम के दिवंगत कर्मचारियों के 46 आश्रितों को जनस्वास्थ्य विभाग में एमटीएस (पब्लिक हेल्थ) के पद पर करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। निगम मुख्यालय स्थित सत्य नारायण बंसल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनकी हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।



महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि निगम कर्मचारियों के हितों और अधिकारों का संरक्षण उसकी प्राथमिकता है। इसी दिशा में कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जनस्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 4000 एमटीएस (पब्लिक हेल्थ) कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत वेतन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, निगम में कार्यरत 1467 स्वच्छता कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर स्वच्छता कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है और उनकी रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। निगम के कर्मचारी दिल्ली में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी मेहनत और योगदान से शहर की सफाई व्यवस्था सहित अन्य नागरिक सेवाएं सुचारु रूप से संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देना और उनके परिवारों को कठिन परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करना निगम की जिम्मेदारी है। करुणामूलक आधार पर दी गई नियुक्तियां इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। इस अवसर पर उप महापौर डॉ. मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव, डीडीए सदस्य राजीव बब्बर, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक रावत सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सिख विरोधी दंगा मामला : जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का बयान दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषिराज शर्मा से क्रास-एग्जामिनेशन किया। सीबीआई के तत्कालीन डीएसपी इमरान आशिक ने आज बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया। इमरान आशिक को पहले भी न्यायालय ने बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था, लेकिन उन्होंने दूसरी तारीख की मांग की थी। न्यायालय ने इमरान आशिक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 20 नवंबर को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके पहले 12 मई को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय अरोड़ा का बयान दर्ज किया गया था। 12 जुलाई, 2025 को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे। हरपाल कौर बेदी ने आरोपित जगदीश टाइटलर की न्यायालय में पहचान की थी। बेदी ने कहा था कि जगदीश टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाकया बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया। टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला। इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपने बयान में कहा था कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह की गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी। जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो,

दिवाली से पहले ही जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्लीवासी, रेखा गुप्ता सरकार की शीतकालीन कार्य योजना विफल: देवेंद्र यादव

नई दिल्ली,सद्भावना टुडे । दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए घोषित शीतकालीन कार्य योजना प्रभावी साबित नहीं हुई है और दिवाली से पहले ही राजधानी के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के साथ-साथ पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार को भी वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। उनके अनुसार, राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 261 तक पहुंच गया है, जबकि आईटीओ, अक्षरधाम, रोहिणी, चांदनी चौक, पंजाबी बाग और जहांगीरपुरी जैसे कई इलाकों में एक्यूआई 300 से 390 के पार दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की यह स्थिति दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा करके औपचारिकता पूरी की है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की घोषणा तभी सार्थक होगी, जब उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। यादव के मुताबिक, प्रदूषित वातावरण का बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।

देवेंद्र यादव ने दावा किया कि रोहिणी में एक्यूआई 396, अलीपुर में 382 और मुंडका में 377 तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ना इस बात का संकेत है कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने को प्रदूषण का प्रमुख कारण बताकर दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उनके अनुसार, सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बावजूद वाहनों से निकलने वाले धुएं, सड़कों की धूल और निर्माण कार्यों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर सालभर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।



कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल और निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन नहीं होना वायु गुणवत्ता बिगड़ने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान केवल अस्थायी उपायों से नहीं हो सकता। यादव ने सरकार से सड़कों की नियमित सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर निगरानी बढ़ाने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

देवेंद्र यादव ने वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि पूरे सप्ताह वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है। उन्होंने इसे दिल्ली के लोगों के लिए गंभीर चेतावनी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शीतकालीन कार्य योजना और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का प्रभाव जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। उनके मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट और योजनाएं बनाने के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की निगरानी तथा परिणामों का सार्वजनिक आकलन भी जरूरी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यमुना नदी की सफाई के मुद्दे पर भी भाजपा और आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि नदी की वास्तविक सफाई सुनिश्चित करने के बजाय राजनीतिक दल प्रतीकात्मक गतिविधियों के माध्यम से लोगों के सामने सकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं।

महादेव बेटिंग ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर दो दिन की सीबीआई ट्रांजिट रिमांड पर

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज निखिल चोपड़ा ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी। सीबीआई अब 6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को रायपुर (छत्तीसगढ़) की विशेष अदालत में पेश करने के लिए ले जाएगी। सौरभ चंद्राकर को एक नवंबर को ही ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। वहां इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के वकील तुषार गिरि ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया था। उनका तर्क था कि उनके मुवक्किल को मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के मामले में प्रत्यर्पित किया गया है, न कि सीबीआई के मामले में। हालांकि, अदालत ने सीबीआई की अर्जी को स्वीकार कर लिया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने भारत के बाहर से ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट का निर्माण और संचालन किया, जिसके लिए उन्होंने देश भर में फैले 'पैनलों' और शाखाओं के एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। आरोप है कि यह गिरोह खेल आयोजनों, ताश के खेलों और अन्य गतिविधियों पर सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करता था, जिसकी आय को बिचौलियों के बैंक खातों और हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा जाता था।

एक नजर

किन्नर बनकर उगाही करने वाली महिलाएं पकड़ी

फरीदाबाद। शहर के नेहरु ग्राउंड में किन्नर बनकर उगाही करने वाली महिलाओं की गैंग को असली किन्नरों ने पकड़ लिया। इस दौरान दो महिलाएं भागने में कामयाब रहीं, जबकि दो को असली किन्नरों ने पकड़ लिया और थाना कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल दोनों थाने में बैठी थीं और इस बाबत किन्नरों की गुरु मनीषा चौहान ने पुलिस में शिकायत दी। मनीषा चौहान ने बताया कि सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि नेहरू ग्राउंड में कुछ नकली किन्नर दुकानदारों से जबरन उगाही कर रहे हैं और पैसे न देने पर उन्हें गालियां दे रहे हैं। सूचना मिलने पर मनीषा चौहान ने कुछ किन्नरों को मौके पर भेजा तो उन्होंने देखा कि चार किन्नर एक वैन में बैठी हुईं थीं, जब उन्होंने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वह महिलाएं है, जो कि किन्नर बनकर लोगों से पैसा उगाह रही थी। इस बीच मौका देखकर दो महिलाएं फरार हो गयीं ,जबकि दो महिलाओं को किन्नरों व स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। किन्नर गुरु मनीषा चौहान ने बताया कि वह टाउन में साल में एक बार यानी दिवाली पर जाते है, जहां लोगों को दुआएं देकर उनकी इच्छा अनुसार दक्षिणा लेती है, लेकिन अगर ऐसे ही नकली किन्नर उनके काम धंधे को प्रभावित करेंगे तो उनके समक्ष भारी परेशानियां हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व कुछ युवकों को भी किन्नर बने हुए पकड़ा गया था, जो बाद में भाग गए थे। बताया गया है कि यह महिलाएं दिल्ली की रहने वाली है और यह काम कब से और क्यों कर रही है, इसकी पूछताछ पुलिस कर रही है।

फरीदाबाद पुलिस का 12वां वीकेंड अभियान, तीन दिन में 116 गिरफ्तार

फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने और जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष वीकेंड अभियान चलाया हुआ है। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक चलाए गए तीन दिवसीय इस अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 116 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 22.720 किलोग्राम गांजा, चार देसी कट्टा, एक कारतूस, 183 बोतल देसी शराब, व जुआ अधिनियम के अंतर्गत एक लाख 47 हजार 450/- रुपए बरामद किये हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न थानों, अपराध शाखाओं और विशेष टीमों ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों, नशा तस्करों, अवैध शराब बेचने वालों तथा जुआ खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा ही है। साथ ही 22 गुमशुदा व्यक्तियों को भी तलाश कर परिजनों से मिलाया है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 22.720 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, वहीं 183 बोतल देसी शराब, 5 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। उन्होंने आगे बताया कि फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं की टीम ने अवैध हथियारों पर कार्रवाई करते अभियान के दौरान 4 देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद किया है। इसी प्रकार जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों गिरफ्तार कर एक लाख 47 हजार 450/- रुपए बरामद किये हैं। उन्होंने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान उद्घोषित अपराधियों और जमानत पर फरार आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से कानून से बचकर घूम रहे 27 आरोपितों पर शिकंजा कसने में मदद मिली। फरीदाबाद पुलिस की आमजन से अपील है कि अपने आसपास किसी भी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

सीएलयू भी नहीं, हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर होते हुए किया जा रहा ढाबे का निर्माण

गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सिधरावली के नजदीक बने मन्नत ढाबा ग्रीन बेल्ट में चल रहा है। साथ ही यह ढाबा बिना सीएलयू (चेंज ऑफ लेंड यूज) चलाया जा रहा है। यह आरोप भोड़ाखुर्द निवासी चंद्रपाल ने यहां पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि मन्नत ढाबा के आसपास उनके परिवार की करीब 830 कनाल 15 मरला जमीन है, जिसमें से करीब दो एकड़ में यह ढाबा बनाया हुआ है। इस ढाबे को ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। चंद्रपाल के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ढाबे समेत पूरी जमीन पर स्टे ऑर्डर जारी किए हुए हैं, लेकिन कोर्ट की अवमानना को लेकर जिला प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस संबंध में दो दिन पहले वे सीएम के जनता दरबार में भी शिकायत दे चुके हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चंद्रपाल ने बताया कि हाई कोर्ट के 18 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश के बावजूद ढाबे में निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे जिला उपायुक्त गुरुग्राम, एसडीएम व डीटीपीई अमित मधोलिया को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इसे सिविल का मैटर कहकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि खुलकर कोर्ट के आदेशों की अवमानना के बावजूद ढाबा संचालकों के पक्ष में रिपोर्ट दे दी जाती है। चंद्रपाल ने बताया कि करीब एक साल पहले आठ नवंबर 2025 को डीटीपीई अमित मधोलिया ने हाईवे के किनारे ढाबों के खिलाफ चार सप्ताह में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

गुरुग्रामः आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाएं महिलाएं- सुनीता दांगी

गुरुग्राम। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दांगी ने सोमवार को गुरुग्राम का दौरा किया। इस दौरान जैकमपुरा स्थित प्रजापति धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हुए ऋण सब्सिडी के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनीता दांगी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार के जरिए आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध



करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इन योजनाओं की जानकारी लेकर इनका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, ताकि वे स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस अवसर पर उन्होंने 34 लाभार्थियों को व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत करीब छह लाख 70 हजार रुपये की ऋण सब्सिडी के चेक वितरित किए।

चेयरपर्सन सुनीता दांगी ने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। हरियाणा महिला विकास निगम इसी उद्देश्य के साथ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें वित्तीय सहायता और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवा रहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी रुचि और कौशल के अनुसार सिलाई, ब्यूटी पार्लर, लघु उद्योग तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शुरू कर सकती हैं। इसके लिए निगम की योजनाएं उनके लिए आर्थिक संबल बनने के साथ अपने सपनों को साकार करने का माध्यम भी हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे केवल योजनाओं की जानकारी तक सीमित न रहें, बल्कि आगे आकर इनका लाभ उठाएं और स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करें।

गुरुग्राम की सभी कॉलोनियों में कराई जा रही फॉगिंगः राजरानी मल्होत्रा

गुरुग्राम। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं मच्छरमुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर की सभी कॉलोनियों में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। महापौर राजरानी मल्होत्रा के निर्देशानुसार मच्छरों की रोकथाम तथा नागरिकों को मच्छरजनित बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

महापौर राजरानी मल्होत्रा स्वयं प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं कॉलोनियों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। इन दौरों के दौरान वह क्षेत्र में साफ-सफाई, कचरा उठान एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र में नियमित सफाई हो तथा नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। महापौर राजरानी मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि गुरुग्राम के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। मच्छरों की रोकथाम के लिए शहर की सभी कॉलोनियों में फॉगिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम की टीमों को लगातार सक्रिय रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना केवल नगर निगम की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। नागरिक अपने आसपास पानी जमा न होने दें, घरों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई बनाए रखें तथा कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें।

चार एंबुलेंस पर 50 लाख का डीजल खर्च, जांच कमेटी हुई गठित

फरीदाबाद। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में महीनों से खड़ी चार एंबुलेंस के नाम पर करीब 50 लाख रुपए का डीजल खरीदे जाने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनएचएम डायरेक्टर वीरेंद्र यादव भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को बीके अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है।

रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, हाल में ही पंचकूला स्थित मुख्यालय ने एम्बुलेंस में फ्यूल कार्ड के जरिए होने वाले लेनदेन की जांच की थी। इस दौरान सामने आया कि कुछ एम्बुलेंस बिना चले ही उनके नाम पर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदा जा रहा था। यह सिलसिला एक-दो बार नहीं, बल्कि लगातार जारी था। जांच में करीब 50 लाख रुपए का ईंधन खरीदे जाने का अंदेशा जताया गया है। खास बात यह है कि जिस अवधि में इन एंबुलेंस के नाम पर डीजल खरीदा गया, उस दौरान वे अपनी निर्धारित जगह से कहीं नहीं गई थीं। विभाग के मुताबिक, एचआर 38जीवी 3491 और एचआर-38 जीवी 9863 नंबर की दो एम्बुलेंस तीन से चार महीने से अस्पताल की मोर्चरी के पास खड़ी थीं। इसके बावजूद 11 अक्टूबर तक इनके फ्यूल कार्ड से डीजल भरवाने की एंट्रियां दर्ज मिलीं। वहीं एचआर38जेड0951 और एचआर38जीवी1670 नंबर की अन्य दो एंबुलेंस जनवरी और अगस्त से एजेंसी की वर्कशॉप में खड़ी थीं। इनके फ्यूल कार्ड से भी 16 सितंबर और 11 अक्टूबर तक डीजल भरवाने का रिकॉर्ड मिला। डिप्टी सिविल सर्जन (एनएचएम) विनय गुप्ता ने 16 अक्टूबर को आरटीएस फ्लीट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में डीजल भरवाने का पूरा ब्योरा, लेनदेन की जानकारी और जिम्मेदार कर्मचारियों के नाम मांगे गए। प्रत्येक एम्बुलेंस के हिसाब से डीजल भरवाने की तारीख, मात्रा, कीमत, पेट्रोल पंप और संबंधित कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बीके अस्पताल के सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने 20 अक्टूबर को मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की।

गाजियाबाद में 4 साल से बंद पड़ा एस्केलेटर जल्द होगा चालू

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मोहननगर तिराहे पर बना एस्केलेटर चार साल बाद फिर से शुरू होगा। इसको लेकर जीडीए और नगर निगम के बीच बातचीत हो गई है। निगम ने जीडीए से एस्केलेटर की मरम्मत कराने और चालू हालत में देने की शर्त दी है। इसके अलावा संचालन संबंधी अन्य शर्तों पर निगम के अधिकारी योजना तैयार कर रहे हैं, जिस पर जीडीए अधिकारियों से जल्द ही वार्ता की जाएगी। जीडीए अधिकारियों का दावा है कि एस्केलेटर के संचालन और रखरखाव के लिए शनिवार को इसे नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया है। इसकी मरम्मत, साफ-सफाई और पेंट का काम पूरा कराने के बाद इसे औपचारिक रूप से नगर निगम के हवाले कर दिया जाएगा।



जीडीए ने साल 2022 में एस्केलेटर को शुरू कराया था। इस पर करीब तीन करोड़ खर्च हुए थे। लगाने के करीब दो महीने में ही यह खराब हो गया। इसके पीछे रखरखाव ठीक से न होना भी कारण रहा। फिलहाल यह बदहाल है और कई जगह से टूटा हुआ है। व्यस्त तिराहे पर रास्ता पार करने में लोगों को जोखिम ही उठाना पड़ रहा है। नगर निगम निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि जन सरोकार का काम नगर निगम करेगा। संचालन पर होने वाले व्यय के लिए आगे वार्ता होनी है। जल्द ही इस पर निर्णय लेकर संचालन कराया जाएगा। चार साल से एस्केलेटर खराब है। इस पर करीब 60 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन लिया गया था।

व्यवसायिक कनेक्शन होने के कारण सालाना करीब लाखों रुपये जीडीए की ओर से चुकाने पड़ रहे थे। इससे बिना चले भी जीडीए को नुकसान हो रहा था। कौशांबी, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम से, यूपी बार्डर से गाजियाबाद जाने वाले और शहर से यूपी बार्डर, वसुंधरा, वैशाली, वसुंधरा और वैशाली जाने वाले लोग मोहननगर तिराहे से गुजरते हैं। रोजाना करीब 35 हजार लोग गुजरते हैं। एस्केलेटर खराब होने के कारण लोगों को सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ने में लोगों को परेशानी होती है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, दिव्यांग और मरीजों को होती है। एस्केलेटर चालू होने के बाद लोगों की समस्या दूर होगी।

गुरुग्राम पुलिस ने मध्य प्रदेश तक फैले अवैध हथियारों के नेटवर्क का किया पर्दाफाश

गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मध्य प्रदेश से हथियारों की खेप लेकर गुरुग्राम पहुंचे दो सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर-40 क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से आठ देशी पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद की हैं। डीसीपी क्राइम नीतीश अग्रवाल के निर्देशन में सेक्टर-40 क्राइम ब्रांच प्रभारी एसआई ललित कुमार के नेतृत्व में एसआई अंकित और उनकी टीम ने एक नवंबर को सोहना-गुरुग्राम रोड पर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के नजदीक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुर्गेश और नरेंद्र उर्फ नरेन के रूप में हुई है।

दोनों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गांव बामनाला के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले करीब चार वर्षों से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और सप्लाई के धंधे में सक्रिय थे। वे मध्य प्रदेश से बस के जरिए हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करते थे और प्रत्येक पिस्टल के बदले सात हजार रुपये कमीशन लेते थे। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का खुलासा 29 अक्टूबर को सेक्टर-112 बजघेड़ा से दीपक और राहुल की गिरफ्तारी के



बाद हुआ था। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच अवैध पिस्टल, 11 मैगजीन और एक कार बरामद की थी।

इसके बाद दोनों आरोपियों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में हथियारों की सप्लाई के स्रोत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस मध्य प्रदेश के खरगोन जिले तक पहुंची। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी कथित तौर पर मध्य प्रदेश में अवैध हथियार तैयार करने वाले व्यक्ति के संपर्क में थे। आरोपियों ने पहले गिरफ्तार दीपक और राहुल को भी पांच पिस्टल तथा 11 मैगजीन सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। इस कार्रवाई के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या चार हो गई है। पुलिस अब तक कुल 13 अवैध पिस्टल और 27 मैगजीन बरामद कर चुकी है।

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो, पेड़ों की छंटाई न होने से लोग बेहाल

साहिबाबाद। टीला मोड़ की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोग सीवर ओवरफ्लो और पेड़ों की छंटाई नहीं होने से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि जीडीए व विद्युत निगम में शिकायत करने के बाद भी इन दोनों समस्याओं से राहत नहीं मिल रही है। अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने बताया कि जगह-जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। इससे सड़कों पर आवागमन में परेशानी हो रही है।

साथ ही घरों के अंदर भी दुर्गंध आ रही है। शिकायत पर जल निकासी और सफाई करा दी जाती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। पेड़ों की छंटाई नहीं होने से भी स्ट्रीट लाइट और बिजली की लाइन कवर हो रही हैं। लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की है। जीडीए के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि सीवर लाइन की सफाई का कार्य किया जा रहा है। जहां भी ओवरफ्लो हैं उससे जल्द राहत मिलेगी।

गुरुग्राम के सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने गंभीरता दिखाई है।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाली तोडफ़ोड़ एवं बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने तथा सरकारी एवं निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने के संबंध में सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त द्वारा सोमवार को जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सीएक्यूएम के निर्देशों का सभी संबंधित विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों, ठेकेदारों, निर्माण एजेंसियों और अन्य प्रतिष्ठानों को तुरंत आवश्यक आदेश जारी करने तथा निर्धारित अवधि के दौरान अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के तहत गुरुग्राम जिले के सभी राज्य सरकार के कार्यालयों एवं निजी कार्यालयों में पांच नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित रहकर काम करना होगा। शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है, जहां कार्य की प्रकृति के कारण वर्क फ्रॉम होम लागू करना संभव नहीं है। यह छूट सीएक्यूएम के आदेश के अनुरूप ही मान्य होगी। जारी निर्देशों के अनुसार पांच नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सीएक्यूएम के आदेश के दायरे में आने वाली सभी धूल पैदा करने वाली तोडफ़ोड़ एवं बाहरी निर्माण गतिविधियां बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध केवल सामान्य भवन निर्माण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी लागू होगा। इसके अंतर्गत हाईवे, सडक़ें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और दूरसंचार संबंधी कार्य भी शामिल हैं।

गुरुग्रामः सीएंडडी वेस्ट डालने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

गुरुग्राम। शहर में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा शहर के सडक़नेटवर्क को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने संबंधित विभागों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सडक़ों की स्थिति सुधारने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे को दुरुस्त एवं बेहतर बनाने तथा वहां सफाई, हरियाली और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) की अवैध डंपिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए एनएचएआई प्रभावी इनफोर्समेंट कार्रवाई सुनिश्चित करे। यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी एक्सप्रेस-वे के आसपास सीएंडडी वेस्ट डालती हुई पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे का रखरखाव, स्वच्छता और हरियाली सुनिश्चित करना एनएचएआई की जिम्मेदारी है। इसलिए संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दें। निगमायुक्त प्रदीप दहिया सोमवार को नगर निगम कार्यालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में नगर निगम गुरुग्राम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), यातायात पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में निगमायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन आने वाली सडक़ों का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाएं।

पत्नी के अफेयर से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दी जान

फरीदाबाद,एजेंसी। पत्नी के अफेयर से परेशान युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे युवक से अफेयर था और दो महीने पहले उसने अपनी पत्नी को उसी युवक के साथ घूमते हुए देखा था। मृतक की छह माह पूर्व ही शादी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच शुरु कर दी है। मृतक की पहचान नेहरू कॉलानी निवासी सतबीर (22) के रुप में हुई है।

उसके चचेरे भाई शिवा ने बताया कि करीब 6 महीने पहले सतबीर और उसके छोटे भाई कमल (20) की शादी हुई थी। सतबीर की पत्नी वंदना और उसका परिवार मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है। फिलहाल वे सेक्टर-22 की मच्छी मार्केट में रह रहे हैं। सतबीर के पिता गोवर्धन बाटा फ्लाईओवर के नीचे जूतों की फड़ लगाते हैं। सतबीर भी उनके साथ काम करता था। शिवा के मुताबिक, सतबीर सुनने और बोलने में असमर्थ था। इसके बावजूद वह पिता के साथ जूते बेचने का काम करता था। उसका छोटा भाई कमल पत्नी के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। मौत से एक दिन पहले उसकी सतबीर से बात हुई थी। वह काफी



समय से परेशान था, क्योंकि पत्नी वंदना मायके से ससुराल लौटने को तैयार नहीं थी। शिवा के मुताबिक, रविवार शाम सतबीर घर के कमरे में अकेला था। उसकी मां बाजार गई हुई थी। वापस लौटने पर वह उसे देखने के लिए ऊपर कमरे में पहुंची तो सतबीर फंदे से लटका मिला। आस-पास के लोगों ने उसे नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवा का आरोप है कि वंदना किसी दूसरे युवक के संपर्क में थी। करीब 2 महीने पहले सतबीर ने दोनों को एक साथ घूमते देख लिया था। इसके बाद वंदना मायके चली गई। सतबीर ने उसे वापस लाने के लिए कई बार मनाया, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं हुई। शनिवार को सतबीर पत्नी को लेने उसके मायके गया था। आरोप है कि वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की।

रामलीला मैदान की इंडी गठबंधन की महारैली के सियासी निहितार्थ को समझिए

कमलेश पांडे

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित इंडी (ड्डह्लष्ठद्ब) गठबंधन की महारैली केवल एक राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि यह विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ड्ढक्र) और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का एक और बृहत प्रयास था। 'वोट बचाओ, देश बचाओ' और 'चलो दिल्ली' के संदेश के साथ आयोजित इस रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई एमएल सहित लगभग 20 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। अधिकांश नेताओं ने गर्मजोशी पूर्वक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई और निज अनुभवजन्य आरोप लगाए। सबसे अंत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संतुलित भाषण देते हुए एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष का परिचय दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए खट्टा मीठा आरोप लगाए, जिसमें ताना और दुलार दोनों शामिल रहा।



इस घटनाक्रम को समझने के लिए अग्रांकित सात महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है:-

पहला, चुनाव आयोग और एसआईआर को विपक्ष ने बनाया मुख्य राजनीतिक मुद्दा: रैली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि विपक्ष ने अपनी लड़ाई को केवल केंद्र सरकार के विरोध तक सीमित न रखकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जोड़ने की कोशिश की। विपक्ष के प्रमुख आरोप हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है।राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इसका राजनीतिक निहितार्थ यह है कि विपक्ष चुनावी निष्पक्षता को अपनी साझा राजनीतिक लड़ाई का आधार बनाना चाहता है। वह मतदाता सूची के विवाद को लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के व्यापक सवाल से जोड़ रहा है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बीच वास्तविक स्थिति का निर्धारण दस्तावेजों, संबंधित मतदाता आंकड़ों और कानूनी जांच के आधार पर ही होना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर (स्ड्ढक्र) के आदेशों को वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप बताया गया है।

दूसरा, विपक्षी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन, लेकिन नेतृत्व का सवाल बरकरार: इस महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं की मौजूदगी महत्वपूर्ण रही। इससे विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रखने वाले दल राष्ट्रीय मुद्दों पर एक मंच पर आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी कायम है: एक, गठबंधन का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में होगा? दो, क्या कांग्रेस और क्षेत्रीय दल एक-दूसरे के राजनीतिक हितों को पर्याप्त जगह देंगे? तीन, क्या विपक्ष साझा मुद्दों पर आंदोलन के साथ-साथ साझा नीतिगत कार्यक्रम भी बना पाएगा? चार, क्या चुनाव के समय सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर सहमति कायम रह सकेगी? इसका सियासी निहितार्थ यह है कि प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा एक मंच पर नेताओं का खड़ा होना और एक साझा राजनीतिक संगठन की तरह काम करना दो अलग-अलग बातें हैं। महारैली ने पहले पहलू को प्रदर्शित किया, जबकि दूसरे की परीक्षा आगे होगी।

तीसरा, कांग्रेस की राष्ट्रीय भूमिका और राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति: रैली के आयोजन में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। खड़गे और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को सामने रखा। राहुल गांधी ने नागरिकों के मताधिकार को धर्म और राजनीतिक पहचान से ऊपर रखने की बात कही। दूसरी ओर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अपने-अपने राज्यों से जुड़े एसआईआर के सवालों को भी उठाया। इस घटनाक्रम के तीन राजनीतिक पहलू हैं: एक, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गतिविधियों का साझा मंच उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। दो, राहुल गांधी के लिए लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता का मुद्दा उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक संवाद शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। तीन, क्षेत्रीय दल इस मंच के माध्यम से अपने राज्य के राजनीतिक मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में जगह दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय भूमिका और गठबंधन के भीतर अन्य दलों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी।

चौथा, ममता, अखिलेश और अन्य क्षेत्रीय नेताओं के अपने राजनीतिक संदेश: महारैली में सभी नेताओं का भाषण एक जैसा नहीं था। जहां अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और कथित नाम कटने के मुद्दे को उठाया। वहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के प्रभाव का विरोध किया। उधर, तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में महाभारत के शकुनि का संदर्भ दिया और पूछा कि आज के कौन है? इसके पीछे उनका गहरा दर्द यह है कि बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनि चौधरी के पुत्र और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर तुषारापात कर दिया। वहीं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक भागीदारी के सवाल उठाए। इससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन का साझा मंच होने के बावजूद उसके प्रत्येक घटक दल की अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में मतदाता सूची, सामाजिक समीकरण और चुनावी प्रतिस्पर्धा के अलग-अलग संदर्भ हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा सभी राज्यों में समान राजनीतिक अर्थ नहीं रखता।

पांचवां, भाजपा और विपक्ष के बीच टकराव अब चुनावी संस्थाओं के सवाल तक पहुंचा: इस रैली के बाद राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी सामने आया कि भाजपा और विपक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक-दूसरे के विरुद्ध अलग-अलग राजनीतिक दावे पेश कर रहे हैं। जहां भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल उठाना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। दिलचस्प बात यह है कि 1 नवंबर को ही दिल्ली के हरिनगर में भाजपा नेता हरदीप सिंह पूरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों के न्याय से जुड़ा अपना विरोध मार्च भी आयोजित किया। इससे रैली के साथ एक अलग राजनीतिक और ऐतिहासिक विवाद भी जुड़ गया। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक विमर्श केवल एसआईआर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें 1984 की त्रासदी, न्याय, राजनीतिक जवाबदेही और विपक्ष की तारीख के चयन जैसे सवाल भी शामिल हो गए।

छठा, क्या महारैली विपक्ष को जनांदोलन में बदलने की क्षमता रखती है?: किसी राजनीतिक रैली की सफलता का आकलन केवल भीड़ के आकार से नहीं किया जा सकता। असली कसौटी यह है कि उसका संदेश कितनी दूर तक पहुंचता है और उसके बाद संगठनात्मक स्तर पर क्या कार्रवाई होती है।

इस दृष्टि से विपक्ष के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं:

एक, मतदाता सूची से जुड़े आरोपों को प्रमाणों के साथ जनता के सामने रखना, क्योंकि घुसपैठियों को निकालने, दो जगहों के वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को हटाने के फैसले को कांग्रेस व उसके समर्थक दल नाजायज़ नहीं ठहरा सकते हैं।

दो, जिन मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायत है, उनके मामलों का तथ्यात्मक समाधान कराना होगा।

तीन, चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियों को संवैधानिक और कानूनी तरीके से उठाना होगा।

चार, साझा राजनीतिक मुद्दों के साथ रोजगार, महंगाई, किसानों, युवाओं और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर भी स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।

पांच, गठबंधन के भीतर नेतृत्व और सीटों के बंटवारे पर व्यावहारिक सहमति बनाना होगा।

छह, यह भी ध्यान रखना होगा कि रैली में उपस्थिति के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दावे और प्रतिदावे सामने आए हैं। इसलिए भीड़ के आधार पर देशव्यापी जनसमर्थन का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

सातवां, इस महारैली से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के सामने क्या सवाल खड़े हुए?: इस घटनाक्रम ने तीन संस्थागत प्रश्नों को चर्चा में ला दिया है: एक, एसआईआर में पारदर्शिता कितनी है? और प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहे। दो, चुनाव आयोग की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो? और चुनावी संस्था पर जनता का विश्वास बना रहे। तीन, राजनीतिक दलों की शिकायतों का समाधान कैसे हो? और विवादों का निष्पक्ष और कानूनी निपटारा हो। यहां पर एक और महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग की आलोचना करना और उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता को कमजोर करना एक ही बात नहीं है। इसी प्रकार आयोग की स्वतंत्रता का सम्मान करने का अर्थ यह भी नहीं कि उसकी प्रक्रियाओं पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों पक्षों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का पालन आवश्यक है।

आखिर इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के भीतर इतनी आक्रामकता कहां से आती है? क्या उसने हिंसा को सामान्य व्यवहार मान लिया है? क्या वह किसी के दर्द और असहायता को महसूस करने की क्षमता खो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हमारे घरों, स्कूलों और समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि बचपन की भाषा में प्रेम और संवेदना की जगह हिंसा प्रवेश करती जा रही है? उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह बच्ची के असहाय हो जाने के बाद भी हमला जारी रहने की बात सामने आई है, वह सामान्य बाल-सुलभ झगड़े से कहीं अधिक गंभीर है। इस घटना ने एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है, जिससे मुंह मोड़ना अब संभव नहीं है कि आखिर बच्चों के मन में हिंसा के बीज कौन बो रहा है? बच्चों और किशोरों में हिंसक व्यवहार का कोई एक कारण नहीं होता। परिवार में हिंसा देखना, कठोर अथवा असंगत अनुशासन, भावनात्मक उपेक्षा, कमजोर अभिभावकीय निगरानी, साथियों का दबाव, सामाजिक अलगाव और व्यवहार पर नियंत्रण की कठिनाइयां इसके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सवाल परिवारों से है। आज अनेक घरों में बच्चों को महंगे खिलौने, स्मार्टफोन, टैबलेट और मनोरंजन के तमाम साधन तो उपलब्ध करा दिए जाते हैं लेकिन उनके साथ बैठकर बातचीत करने, उनकी भावनाएं समझने और उनके व्यवहार को दिशा देने का समय लगातार कम होता जा रहा है।

किताबों और खिलौनों की उम्र में हिंसा का पाठ क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे?

योगेश कुमार गोयल

बचपन को मासूमियत, निश्छलता, संवेदनशीलता और खिलखिलाती मुस्कान का पर्याय माना जाता है। बच्चों के हाथों में खिलौने अच्छे लगते हैं, पत्थर और ईंटें नहीं, उनकी आंखों में सपने अच्छे लगते हैं, किसी के प्रति नफरत और हिंसा नहीं। लेकिन जब 8-10 वर्ष की उम्र के बच्चे भी किसी दूसरे मासूम की जान लेने पर उतारू हो जाएं, तब सवाल केवल एक बच्चे के असामान्य व्यवहार का नहीं रह जाता बल्कि पूरे सामाजिक परिवेश, पारिवारिक संस्कारों, शिक्षा व्यवस्था और हमारी बदलती जीवनशैली का हो जाता है। हरियाणा के पंचकूला में छह साल की विशेष आवश्यकता वाली बच्ची पर तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र द्वारा किया गया बर्बर हमला इसी भयावह वास्तविकता का आईना है। जब पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में हुई इस हृदयविदारक घटना का वीडियो देखा तो मन बेहद विचलित हो उठा। आरोपी छात्र बच्ची को एक खाली कक्षा में ले गया, वहां उसके बाल पकड़कर घसीटा, बेंच पर सिर पटका, लातें मारी तथा ईंट, पत्थर और गमले से उसके सिर तथा चेहरे पर बार-बार प्रहार किए। करीब 96 सैकेंड तक चली इस हिंसा का दृश्य कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ। सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि हमला करने वाला कोई व्यस्क अपराधी नहीं बल्कि 8 वर्ष का बच्चा है। यह घटना जितनी पीड़ित बच्ची के लिए भयावह है, उतनी ही उस बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। आखिर इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के भीतर इतनी आक्रामकता कहां से आती है? क्या उसने हिंसा को सामान्य व्यवहार मान लिया है? क्या वह किसी के दर्द और असहायता को महसूस करने की क्षमता खो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हमारे घरों, स्कूलों और समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि बचपन की भाषा में प्रेम और संवेदना की जगह हिंसा प्रवेश करती जा रही है? उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह बच्ची के असहाय हो जाने के बाद भी हमला जारी रहने की बात सामने आई है, वह सामान्य बाल-सुलभ झगड़े से कहीं अधिक गंभीर है।



इस घटना ने एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है, जिससे मुंह मोड़ना अब संभव नहीं है कि आखिर बच्चों के मन में हिंसा के बीज कौन बो रहा है? बच्चों और किशोरों में हिंसक व्यवहार का कोई एक कारण नहीं होता। परिवार में हिंसा देखना, कठोर अथवा असंगत अनुशासन, भावनात्मक उपेक्षा, कमजोर अभिभावकीय निगरानी, साथियों का दबाव, सामाजिक अलगाव और व्यवहार पर नियंत्रण की कठिनाइयां इसके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सवाल परिवारों से है। आज अनेक घरों में बच्चों को महंगे खिलौने, स्मार्टफोन, टैबलेट और मनोरंजन के तमाम साधन तो उपलब्ध करा दिए जाते हैं लेकिन उनके साथ बैठकर बातचीत करने, उनकी भावनाएं समझने और उनके व्यवहार को दिशा देने का समय लगातार कम होता जा रहा है। माता-पिता अपनी व्यस्तताओं में उलझे हैं और कई बार बच्चे अपनी भावनात्मक उलझनों के साथ अकेले रह जाते हैं। घर में माता-पिता के झगड़े, गाली-गलौज, मारपीट, अपमानजनक भाषा और छोटी-छोटी बातों पर हिंसक प्रतिक्रिया देखने वाले बच्चों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बच्चा वही सीखता है, जो अपने आसपास बार-बार देखता है। यदि घर में समस्या का समाधान संवाद से नहीं बल्कि चीखने, धमकाने और हाथ उठाने से होता है तो उसके लिए हिंसा धीरे-धीरे व्यवहार का स्वीकार्य तरीका बन सकती है।

दूसरा बड़ा सवाल डिजिटल दुनिया का है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने बच्चों के सामने ज्ञान और मनोरंजन के असंख्य अवसर खोले हैं लेकिन इसी दुनिया में हिंसक वीडियो, मारधाड़ वाले खेल, अपमानजनक सामग्री और आक्रामक व्यवहार को महिमामंडित करने वाले दृश्य भी मौजूद हैं। समस्या तब गंभीर हो जाती है, जब बच्चा बिना किसी निगरानी के घंटों ऐसी सामग्री देखता है और उसे यह समझाने वाला कोई नहीं होता कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली हिंसा वास्तविक जीवन में किसी के शरीर, मन और अस्तित्व को कितनी गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरी चिंता बच्चों में संवेदनशीलता और सहानुभूति के विकास की है। आज हम बच्चों को प्रतियोगिता में आगे निकलना, जीतना और दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना तो सिखा रहे हैं लेकिन हार स्वीकार करना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, कमजोर की मदद करना और क्रोध पर नियंत्रण रखना कितना सिखा रहे हैं? क्या स्कूलों में नैतिक शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सिमट गई है? क्या बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि किसी को चोट पहुंचाना बहादुरी नहीं, कमजोरी है? किसी दूसरे की पीड़ा देखकर मन में करुणा पैदा होना ही मानवीय संवेदना का आधार है। यदि यही संवेदना विकसित नहीं होगी तो शिक्षा की बड़ी-बड़ी डिग्रियां भी सभ्य समाज की गारंटी नहीं बन सकतीं। यहां स्कूलों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पंचकूला की घटना ने सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी और वास्तविक निगरानी के बीच के अंतर को उजागर किया है। कैमरे लगे होना सुरक्षा नहीं है, उनकी सतत निगरानी, समय पर हस्तक्षेप और जवाबदेही ही सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सवाल है कि एक छह साल की बच्ची स्कूल परिसर में एक अन्य छात्र के साथ ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गई, जहां उस पर लगातार हमला होता रहा और किसी शिक्षक या कर्मचारी को समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिली? यदि स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, एक शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी अथवा ड्यूटी व्यवस्था में कोई खामी थी तो यह भी जांच का विषय है। यह पहली घटना नहीं है, जब स्कूलों में बच्चों के बीच हिंसा ने पूरे देश को झकझोरा हो। वर्ष 2017 में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या, 2018 में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में चाकूबाजी, 2019 में तमिलनाडु के कोडईकनाल में क्रिकेट विवाद के बाद छात्र की हत्या, 2021 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में छात्र की चाकू मारकर हत्या, 2025 में अहमदाबाद में छात्र की हत्या और 2026 में सूरत में स्कूल परिसर में चाकूबाजी जैसी घटनाएं अलग-अलग समय पर सामने आ चुकी हैं। इन सभी मामलों की परिस्थितियां अलग हैं लेकिन एक बात समान है कि स्कूल, जिन्हें बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, वहां भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब समय आ गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग स्कूलों की सुरक्षा को केवल औपचारिक निरीक्षण और कागजी दिशा-निर्देशों तक सीमित न रखें। प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक, प्रशिक्षित काउंसलर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित सहयोगी कर्मचारी, संवेदनशील स्थानों पर सतत निगरानी और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चों के व्यवहार में अचानक आक्रामकता, दूसरों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति, क्रोध पर नियंत्रण न रहना, पश्चाताप का अभाव, जानवरों अथवा कमजोर बच्चों के प्रति क्रूरता जैसे संकेतों को सामान्य शरारत समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को दंडित करने के बजाय उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर देना और प्रेम के साथ स्पष्ट अनुशासन सिखाना जरूरी है। खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियां, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक सेवा जैसी गतिविधियां भी उनमें सहयोग, धैर्य और सहानुभूति विकसित कर सकती हैं।

विचार

सियासी शक्ति प्रदर्शन की कीमत चुका रहे दिल्ली के व्यापारी

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

धनतेरस, दीपावली और भाईदूज! देश के व्यापारियों के लिए सालभर की कमाई का सबसे महत्वपूर्ण समय। बाजारों में ग्राहकों की भीड़, दुकानों पर खरीदारी की रौनक, गोदामों से निकलता सामान, सड़कों पर दौड़ते मालवाहक वाहन और दिन-रात मेहनत करते हजारों मजदूर। दिल्ली के बाजार भी इसी कारोबारी उत्साह के साथ त्योहारों का स्वागत कर रहे हैं, तभी इसी निर्णायक कारोबारी दौर में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की महारैली ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि व्यापारियों के सामने दुकानें खोलने और ग्राहकों तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) का दावा है कि रैली के चलते करीब 2.5 लाख दुकानें बंद रहीं और लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर चोट पहुंची। प्रश्न राहुल गांधी से सीधा है, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए आयोजित इस रैली की आर्थिक कीमत आखिर दिल्ली के व्यापारी, दुकानदार और रोज कमाकर परिवार पालने वाले मजदूर क्यों चुकाएं?

लोकतंत्र में अपनी बात जनता तक पहुंचाने, सरकार का विरोध करने और राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सभाएं होनी चाहिए, मगर क्या लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के इस अधिकार का अर्थ यह है कि शहर की आर्थिक गतिविधियों को ठप करने की कीमत आम नागरिकों से वसूली जाए? जिस समय दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की सबसे अधिक आवाजाही होनी चाहिए थी, उस समय व्यापारियों को दुकानें बंद रखने, ग्राहकों के इंतजार और माल की आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस संकट ओर ध्यान भी पहले दिला दिया था कि रामलीला मैदान के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, कश्मीरी गेट और भगीरथ पैलेस सहित 22 से 25 प्रमुख बाजार आते हैं। इन बाजारों में लगभग तीन लाख दुकानें हैं, जिनमें से करीब 2.5 लाख दुकानें हैं, ऐसे में कृपया अभी यहां रैली न की जाए, पर व्यापारियों के हित की बात कांग्रेस को कहां सुनाई देनी थी? सबसे गंभीर बात यह है कि सदर बाजार से देशभर में घरेलू सामान की आपूर्ति होती है, चांदनी चौक कपड़ों और आभूषणों का बड़ा केंद्र है, खारी बावली मसालों और सूखे मेवों के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है और भगीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक सामान का महत्वपूर्ण बाजार है। इन बाजारों से देश के विभिन्न राज्यों के हजारों छोटे-बड़े व्यापारी जुड़े हैं। रैली से पहले लगभग दस लाख लोगों के जुटने और 15 से 20 हजार वाहनों के दिल्ली पहुंचने की आशंका ने ही व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता पैदा कर दी थी। सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, रास्तों में बदलाव और संभावित जाम की खबरों से बाजार आने वाले ग्राहकों ने अपनी खरीदारी की योजना टाल दी। राहुल गांधी ने रैली के दौरान लोगों से दिल्ली के बाजारों में जाकर खरीदारी करने और व्यापारियों का समर्थन करने की अपील की। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, मगर इसकी जमीनी हकीकत पर भी विचार होना चाहिए। जब करीब 80 प्रतिशत दुकानें बंद थीं, बाजारों तक पहुंचने के रास्ते प्रभावित थे और ग्राहक आने से बच रहे थे, तब खरीदारी की अपील का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है? वास्तव में व्यापारियों का सवाल भी यही था कि जब दुकानें ही बंद थीं तो ग्राहक खरीदारी कहां करते? राजनीतिक मंच से व्यापारियों के प्रति सहानुभूति जताना और उनकी वास्तविक कारोबारी परिस्थितियों को समझना दो अलग-अलग बातें हैं। सीटीआई ने रैली वाले दिन कारोबार सामान्य पीक सीजन की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत तक सिमटने की बात कही है। लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के कारोबार को नुकसान हुआ है। अब इससे जुड़ी आर्थिक चिंता को खारिज करना भी संभव नहीं है। क्योंकि छोटे दुकानदारों के लिए त्योहारों की बिक्री महज मुनाफा कमाने का अवसर नहीं होती, यह उनके पूरे साल के वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण आधार होती है। कई कारोबारी उधार पर माल खरीदते हैं। त्योहारों में होने वाली बिक्री से आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करते हैं, कर्मचारियों का वेतन देते हैं और अगली खेप के लिए पूंजी जुटाते हैं। बिक्री के महत्वपूर्ण दिन निकल जाने पर उनकी आर्थिक गणना बिगड़ जाती है। त्योहार बीतने के बाद कई वस्तुओं की मांग तेजी से घट जाती है। इस रैली की कीमत उन लोगों ने भी चुकाई, जिनकी आवाज राजनीतिक मंचों तक शायद ही कभी पहुंचती है। दिल्ली के बाजारों में माल उतारने, पैकिंग करने, सामान पहुंचाने और गोदामों में काम करने वाले हजारों मजदूर रोज की कमाई पर निर्भर रहते हैं। सामान्य त्योहारी दिनों में इन बाजारों में चार लाख से अधिक मजदूरों को काम मिलता है, जबकि रैली वाले दिन काम करने वालों की संख्या एक लाख से कम रह गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से आए मजदूर त्योहारों के दिनों में अतिरिक्त मेहनत करके अपने परिवारों के लिए कुछ अधिक कमाने की उम्मीद रखते हैं।

मुख्यमंत्री ने गडकरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाने का किया आग्रह

- 49,751 करोड़ रुपये की चार प्रमुख परियोजनाएं सीसीईए की अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित
- गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे को शीघ्र अधिसूचित करने का आग्रह



नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री के आवास पर हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द शुरू करने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर सहयोग देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बिहार की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली प्रमुख सड़क परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में कुल 49,751 करोड़ रुपये की लागत वाली और लगभग 330 किलोमीटर लंबाई की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) से मंजूरी मिल चुकी है। ये परियोजनाएं राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में 1,976.77 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-727एए पर गंडक नदी में दो लेन के पुल और पहुंच पथ का निर्माण शामिल है। यह पुल बिहार के मनुआपुल (बेतिया) को उत्तर प्रदेश के तिवारीपट्टी (सेवराही) से जोड़ेगा। इसके अलावा 8,455.86 करोड़ रुपये की लागत से सरिस्ताबाद-दीदारगंज और अनीसाबाद-दीदारगंज खंड में छह लेन का एलिवेटेड मार्ग एवं सर्विस रोड बनाया जाना है। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर प्रस्तावित है। अन्य परियोजनाओं में 31,987.11 करोड़ रुपये की लागत से पटना-पूर्णिया चार लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (एनएच-09) तथा 7,331.40 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी-रांची-कोलकाता छह लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण शामिल है। वाराणसी-रांची-कोलकाता हाईवे के तहत कोणकी गांव से लेरुआ गांव तक का खंड हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जाना है। बैठक में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के बिहार खंड को राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे के रूप में जल्द अधिसूचित करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निर्माण-पूर्व कार्यों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पूरा सहयोग दे रही है। संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए 3ए अधिसूचना की प्रक्रिया भी उन्नत चरण में है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से उत्तर बिहार में नदियों पर नए पुल बनेंगे और राज्य की यातायात व्यवस्था को व्यापक लाभ मिलेगा। सम्राट चौधरी ने रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के संशोधित मार्ग को मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना नेपाल के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और हल्दिया बंदरगाह से बिहार की सीधी संपर्कता स्थापित करने के लिहाज से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस एक्सप्रेस-वे को जल्द अधिसूचित कर स्वीकृति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर-बरौनी (एनएच-122) के चार लेन में चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि एनएचएआई इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में रखरखाव एवं विकास के लिए लगभग 2,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के पथ निर्माण विभाग को सौंपे गए हैं। विभाग ने 323 किलोमीटर लंबाई की छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 13,015 करोड़ रुपये है। इनमें विक्रमशिला पुल का पहुंच पथ और मशरख-चकिया-भिट्ठामोड़ चार लेन चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को जल्द तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति देने का आग्रह किया।

एक नजर

दरभंगा में औषधीय पौधों की क्लस्टर आधारित खेती को मिलेगा बढ़ावा

दरभंगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने दरभंगा जिले में केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 'एकीकृत औषधीय पादप विकास परियोजना' को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इसके तहत जल्द ही जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता की विशेषज्ञ टीम दरभंगा का दौरा कर औषधीय पौधों की क्लस्टर आधारित खेती की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी। स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सीईओ डॉ. महेश कुमार दाधीच के निर्देश पर जादवपुर विश्वविद्यालय के पूर्वी क्षेत्रीय सुविधा केंद्र ने इस दिशा में पहल शुरू की है। विशेषज्ञ टीम जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थलीय सर्वेक्षण कर किसानों से संवाद करेगी। साथ ही मिट्टी, जलवायु और जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त औषधीय फसलों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत कालमेघ, अश्वगंधा, शतावरी, सर्पगंधा, तुलसी, गिलोय, पिपली, ब्राह्मी और लेमनग्रास की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उन्नत नर्सरी, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन की सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है। डॉ. ठाकुर ने कहा कि इस पहल से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ युवाओं, महिलाओं और कृषक उत्पादक संगठनों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

सारण पुलिस ने 24 घंटे में 14 वारंटी सहित 55 आरोपितों को किया गिरफ्तार

सारण। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 55 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस की इस कार्रवाई में अलग-अलग मामलों में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में वारंट में चौदह, शराब सेवन में तेरह, शराब कारोबारी में छह, एनडीपीएस एक्ट में तीन, हत्या के प्रयास में तीन, अपहरण में एक डकैती में एक आर्म्स एक्ट में एक पोक्सो एक्ट में एक और अन्य मामलों में बारह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने 470.1 लीटर शराब जिनमें 436.800 लीटर देशी एवं 33.300 लीटर विदेशी शराब जब्त करने के साथ-साथ मोटरसाइकिल तीन, स्कूटी एक, ताला एक, हसुआ एक, देसी कट्टा एक, कारतूस पांच, छह ग्राम स्मैक एवं अपहर्ता दो बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपहृताओं को भी बरामद किया है। यातायात सुरक्षा और अपराध रोकथाम को लेकर चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के तहत 15 वाहनों से कुल 34000 रुपये अर्थदण्ड भी वसूला।

सारण में खेत बचाओ अभियान का आयोजन, कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण पर दिया विशेष जोर

सारण। जिले के भिखारी ठाकुर प्रेक्षा गृह में खेत बचाओ अभियान-सह-कृषि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे परिवार का स्वास्थ्य सीधे हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। उपजाऊ और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी ही शुद्ध, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ समाज का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यह अभियान धरती की उर्वरता बचाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का बड़ा संकल्प है। स्कूल स्तर पर मृदा स्वास्थ्य के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए कृषि मंत्री ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के सभी 38 जिलों के 629 पीएम श्री एवं राजकीय विद्यालयों में मिनी मिट्टी जाँच प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी। इनमें से 160 विद्यालयों में यह सुविधा पहले ही स्थापित हो चुकी है। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में राज्यभर में 7,275 किसान बैठकों के जरिए 6,19,436 किसानों जिनमें 2,12,610 महिलाएँ शामिल हैं को जोड़ा गया। वहीं आगामी रबी मौसम 2026-27 में सभी 534 प्रखंडों में विशेष शिविर लगाकर 15 से 16 लाख किसानों तक सीधे पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान श्री सिन्हा ने बीज, कीटनाशक, उर्वरक एवं मिट्टी जाँच सहित 19 महत्वपूर्ण विषयों पर किसानों के साथ सीधा संवाद किया और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कृषि विभाग द्वारा लगाई गई आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर महराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, छपरा विधायक छोटी कुमारी, तरैया विधायक जनक सिंह, मांझी विधायक रंधीर कुमार सिंह, एकमा विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह तथा विधान परिषद सदस्य सच्चिदानंद राय, जिला अध्यक्ष उमेश तिवारी जिला, अध्यक्ष रणजीत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीन

भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने के उपरांत उनके भागलपुर प्रथम आगमन पर खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह फकरे आलम हसन ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान सज्जादा नशीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और दुआएं पेश कीं। इस अवसर पर खानकाह से जुड़े कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान सज्जादा नशीन सैयद शाह फकरे आलम ने कहा कि भाजपा का प्रसिद्ध नारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' अपने भीतर एक व्यापक राष्ट्रीय संदेश समेटे हुए है। आवश्यकता इस बात की है कि इस नारे को केवल भाषणों, घोषणाओं और राजनीतिक मंचों तक सीमित न रखकर व्यावहारिक धरातल पर पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता के साथ साकार किया जाए। देश के प्रत्येक धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों के दिलों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि सरकार और राजनीतिक नेतृत्व की नजर में सभी नागरिक समान हैं तथा विकास, सम्मान, सुरक्षा व अवसरों पर सबका बराबर अधिकार है। देश में अराजकता के विरोध और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित रैली के संदर्भ में सज्जादा नशीन ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में देश के भीतर अराजकता, अशांति, हिंसा या नफरत का वातावरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का विरोध या समर्थन करना नहीं, बल्कि देश में अमन, शांति, भाईचारे, न्याय और मानवता के मूल्यों को मजबूत करना है। हमारा देश तभी मजबूत होगा, जब समाज के सभी वर्ग राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ेंगे।' उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन अपने नए दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

मुजफ्फरपुर में पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से धमाका, एक व्यक्ति की मौत, छह घायल

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही-डुमरी इलाके में सोमवार को नाला निर्माण के दौरान जेसीबी से खुदाई करते समय भूमिगत पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गैस रिसाव के बाद जोरदार धमाका हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए हैं। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने मीडिया को बताया कि मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र की श्रीनगर कॉलोनी, मकान संख्या 1/5 निवासी निवास सिंह (पिता-श्याम नंदन चौधरी) के रूप में हुई है। हादसे में घायल छह लोगों को गोबरसही स्थित निजी आशा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता आबकारी विभाग में दरोगा पद से सेवानिवृत्त हैं और निवास सिंह विज्ञान विषय के कोचिंग संचालक थे। वह स्कूटी से अपने बेटे की फीस जमा करने जा रहे थे, तभी हादसे की चपेट में आ गए।

घायलों की पहचान मुकेश कुमार (20), सोनम कुमारी (36), मोहम्मद अयान (17), रुकसाना खातून (40), विजय राम (32), और विकास कुमार (27) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर एसडीएम पूर्वी आनंद उत्सव, टाउन-2 के सीडीपीओ दीपक कुमार और जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रज्ञा शरण समेत अन्य अधिकारियों ने स्थिति संभाली। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना पर केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरपुर के सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए इसे अत्यंत दुखद घटना बताया। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता देने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सांसद ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

फरक्का जल संधि के कारण बिहार में जलसंकट, नवीनीकरण मंजूर नहीं: संजय झा



पटना। बिहार के लखीसराय जिले से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के ''फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद'' कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हुआ। कार्यक्रम के तहत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का गंगा किनारे बसे बिहार के उन 12 जिलों में संवाद निर्धारित है, जो इस संधि के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। उल्लेखनीय है कि संवाद कार्यक्रम के पहले चरण में बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिले, तो दूसरे चरण में सारण, वैशाली, समस्तीपुर और पटना जिले शामिल थे। तीसरे चरण का आगाज लखीसराय से हुआ। इसके बाद मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में संवाद कार्यक्रम निर्धारित है। बिहार में गंगा बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। यही कारण है कि इस जन-जागरुकता अभियान का शुभारंभ 5 सितंबर को बक्सर से हुआ, जबकि समापन 4 नवंबर को कटिहार में होगा।

मौके पर लखीसराय के टाउन हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विधायक रामानंद मंडल एवं जिलाध्यक्ष रामानुज शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर पार्टी की ओर से तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म खास तौर से दिखाई गई। साथ ही विस्तृत जानकारी वाला पम्फलेट भी बांटा गया। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई यह संधि भारत के, खासकर बिहार के हित में नहीं है, इसलिए इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए और अगर कोई संधि होती भी है तो बिहार की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस जल संधि के कारण बिहार का जल-प्रबंधन बुरी तरह बिगड़ा है और हम गंभीर जल-संकट का सामना कर रहे हैं। संजय कुमार झा ने कहा कि इस संधि के कारण शुष्क मौसम में सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि बिहार की आंतरिक नदियों से भी पानी खींचकर बांग्लादेश को दिया जाता है। बिहार और केन्द्र की तत्कालीन सरकार में बैठे लोगों ने बिहार के हितों की बलि चढ़ा दी। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि ऐसा करके वे बिहार के किसानों की सिंचाई, लोगों का पेयजल, उद्योगों की पानी की जरूरत, लाखों लोगों की आजीविका और राज्य के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं।

पीएम श्री नवोदय विद्यालय कोलासी में जिला स्तरीय युवा कला उत्सव का भव्य आयोजन, लोककला व प्रतिभाओं का दिखा संगम



कटिहार,एजेंसी। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कोलासी के बहुउद्देशीय सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय युवा कला उत्सव-2026 का गरिमामय आयोजन किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन कटिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में जिले की युवा प्रतिभाओं, समृद्ध लोकपरंपरा और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उत्सव के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आईं छात्राओं और युवाओं ने लोकनृत्य, लोकगीत और नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक स्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से बिहार की समृद्ध लोकसंस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया, जिसे देखकर सभागार में मौजूद दर्शक व अतिथि भावविभोर हो गए।

प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और शानदार कला का प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को मंचासीन अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। अतिथियों ने छात्राओं के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवा कलाकारों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का संबल मिलता है। समारोह में मुख्य रूप से बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, उप विकास आयुक्त (डीडीसी) डॉ. नेहा कुमारी, कोढ़ा विधायक कविता पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह, नगर निगम महापौर उषा अग्रवाल, कला एवं संस्कृति विभाग की जिला प्राधिकारी रीना कुमारी तथा जेएनवी प्राचार्य डॉ. हरे राम कुमार उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से युवा पीढ़ी को सृजनात्मक कार्यों से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. मनोरंजन कुमार ने बताया कि कला उत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय संस्कृति और लोककलाओं के प्रति रुचि और सम्मान पैदा करना है। उन्होंने कहा कि कला सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक गीता कुमारी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, कला प्रेमी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

राम मंदिर आंदोलन के बलिदानी कोठारी बंधुओं की स्मृति में विहिप-बजरंग दल ने लगाया रक्तदान शिविर



कटिहार। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) एवं बजरंग दल, कटिहार के संयुक्त तत्वावधान में राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी कोठारी बंधुओं की पावन स्मृति में 'हुतात्मा दिवस' पर एक विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत शुभारंभ बजरंग दल के नगर विद्यार्थी प्रमुख कुणाल जोशी ने परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं और संगठन के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का अनुकरणीय संदेश दिया।

इस अवसर पर नगर विद्यार्थी प्रमुख कुणाल जोशी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में कोठारी बंधुओं का सर्वोच्च बलिदान देश की युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके बताए आदर्शों पर चलते हुए समाज व राष्ट्र की सेवा करना ही प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। रक्तदान को महादान बताते हुए उन्होंने कहा कि शिविर में दान किया गया रक्त आपातकाल में किसी जरूरतमंद की अनमोल जिंदगी बचा सकता है। वहीं, सह विद्यार्थी प्रमुख बादल रमानी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्र सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुतात्मा दिवस के अवसर पर आयोजित यह रक्तदान शिविर युवाओं के भीतर राष्ट्रभक्ति और निस्वार्थ सेवा की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करता है। यह पूरा आयोजन विहिप के पूर्व विभाग संयोजक सह समाजसेवी पवन पोद्दार के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर के समापन पर सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रांत सुरक्षा प्रमुख अनीश सिंह, विभाग संयोजक सत्यम, विभाग सेवा प्रमुख विष्णु शांडिल्य, जिला मंत्री प्रीतम प्रताप सिंह, जिला सह मंत्री प्रणव भगत, जिला सेवा प्रमुख राजेश राज, बलोपासना प्रमुख रंजन, राजा सिंह, रौनक कुमार एवं अंकित सिंह सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

एक नजर

किमी एंटोनेली के पहले फॉर्मूला-1 विश्व चैंपियन बनने पर स्टेफानो डोमेनिकली ने दी बधाई



नई दिल्ली। फॉर्मूला-1 के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेफानो डोमेनिकली ने किमी एंटोनेली को पहली बार ड्राइवर विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी है। उन्होंने एंटोनेली की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में विश्व चैंपियन बनना उनकी असाधारण प्रतिभा, साहस और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। डोमेनिकली ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि एंटोनेली को विश्व चैंपियन बनते देखना उनके लिए गर्व का क्षण है। वह 1953 में अल्बर्टो अस्कारी के बाद फॉर्मूला-1 विश्व चैंपियन बनने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी हैं। इटली ने इस उपलब्धि के लिए 73 वर्षों तक इंतजार किया है और अब पूरा देश अपने इस खिलाड़ी की सफलता का जश्न मनाएगा। उन्होंने कहा कि महानता केवल रिकॉर्ड बनाने से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने से भी तय होती है। एंटोनेली ने दुनियाभर के लाखों प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को दिखाया है कि समर्पण, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। डोमेनिकली ने कहा कि आज एंटोनेली का नाम इस खेल के दिग्गजों की सूची में शामिल हो गया है। फॉर्मूला-1 के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है और उन्हें विश्वास है कि यह एंटोनेली के शानदार करियर की सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए एंटोनेली, मर्सिडीज टीम और उनके परिवार को बधाई दी। साथ ही कहा कि पूरा फॉर्मूला-1 समुदाय इस खास उपलब्धि का जश्न मनाने में उनके साथ है।

ब्रिटिश नागरिक के रूप में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में शामिल हुए मोहम्मद आमिर

दुबई। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (एपीएल) के ड्राफ्ट के लिए ब्रिटेन के नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया है। यह ड्राफ्ट मंगलवार, 3 नवंबर को दुबई में आयोजित होगा। भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर विजय शंकर और केएस भरत ने भी इस ड्राफ्ट के लिए पंजीकरण कराया है। दोनों खिलाड़ी सभी प्रारूपों के क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। लीग का आयोजन इस साल के अंत में होने की संभावना है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार 34 वर्षीय आमिर पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं और फिलहाल इंग्लैंड में रहते हैं। वह पहले ही ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर चुके हैं। ड्राफ्ट की सूची में उन्हें औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है, जबकि उनके निवास का देश पाकिस्तान दर्ज है। आमिर को ड्राफ्ट की प्लेटिनम श्रेणी में रखा गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आमिर इंग्लैंड से ही आईपीएल नीलामी के लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अजहर महमूद ब्रिटिश पासपोर्ट के आधार पर 2012 से 2015 के बीच आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल चुके हैं। पाकिस्तान के नागरिकों पर प्रतिबंध के बावजूद उन्हें लीग में खेलने का मौका मिला था। आमिर में कोई फ्रेंचाइजी दिलचस्पी दिखाती है या नहीं, इसका पता 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली आईपीएल की मिनी नीलामी के दौरान चलेगा। आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 एकदिवसीय और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच जून 2024 में आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा के लॉडरहिल में आईसीसी टी20 विश्व कप के दौरान खेला था।

ब्रिटेन के नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने का आमिर को तत्काल लाभ यह मिल सकता है कि उन्हें अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की जरूरत न पड़े। हालांकि, पाकिस्तान के उनके पूर्व साथी खिलाड़ियों के लिए एनओसी मिलना तय नहीं है। डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा कूटनीतिक तनाव के कारण यह सवाल बना हुआ है कि पीसीबी अपने खिलाड़ियों को एपीएल में खेलने की अनुमति देगा या नहीं। ड्राफ्ट के पंजीकरण में फखर जमां, साइम अयूब, हसन अली, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ और इमाद वसीम समेत 30 से अधिक पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि, पीसीबी के एक प्रवक्ता ने एपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों को एनओसी दिए जाने की संभावना पर संदेह जताया है। विजय शंकर, अयान खान और मुरुगन अश्विन ने भारतीय खिलाड़ी के रूप में पंजीकरण कराया है, जबकि केएस भरत को संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय खिलाड़ी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विजय, मुरुगन और भरत को ड्राफ्ट की गोल्ड श्रेणी में रखा गया है।

कोरिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे लक्ष्य सेन

नई दिल्ली। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 3 से 8 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के येओसु शहर में स्थित स्टेडियम में होगा। पांच लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाले इस बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट में कई भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। जर्मनी में हायलो ओपन का खिताब जीतकर पहुंचे पांचवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन पुरुष एकल में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य अपने अभियान की शुरुआत चीन के डोंग तियान याओ के खिलाफ करेंगे। वहीं, एचएस प्रणय का सामना दक्षिण कोरिया के यू ताए बिन से होगा। तरुण मन्नेपल्ली और रौनक चौहान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। महिला एकल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की मनामी सुजुई से होगा। मालविका बंसोड़ के सामने चौथी वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की सिम यू जिन की चुनौती होगी। वहीं, अनमोल खरब कनाडा की रेचल चैन के खिलाफ उतरेंगी। हायलो ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अनमोल की कोशिश यहां भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की होगी। महिला एकल में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन से यंग प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। हायलो ओपन का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु ने कोरिया ओपन और जापान मास्टर्स, दोनों प्रतियोगिताओं से हटने का फैसला किया है। पुरुष युगल के क्वालीफाइंग दौर में अर्जुन रेड्डी पोचाना और अच्युतादित्य राव दोड्डावरापु की जोड़ी हिस्सा लेगी।

आर्सेनल ने 14 साल बाद एनफील्ड में दर्ज की जीत, ब्राइटन ने मैनचेस्टर सिटी को उसी के घर में हराया

लंदन,एजेंसी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2026-27 के नौवें सप्ताह में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां और दिलचस्प रिकॉर्ड देखने को मिले। आर्सेनल ने लिवरपूल को उसके घरेलू मैदान एनफील्ड में 1-0 से हराकर 2012 के बाद पहली जीत दर्ज की। ब्राइटन ने पहली बार मैनचेस्टर सिटी को उसके घर में शिकस्त दी। चेल्सी के कोल पामर ने भी प्रीमियर लीग में अपने 50 गोल पूरे किए। टोटेनहम ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 34 शॉट लगाकर अपना दबदबा दिखाया।

आर्सेनल ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर एनफील्ड में 2012 के बाद पहली बार जीत हासिल की। इससे पहले आर्सेनल ने लिवरपूल के मैदान पर लगातार 16 मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं की थी। नौ मैचों में 24 अंक हासिल करने वाली आर्सेनल इस सत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही है। प्रीमियर लीग के किसी भी क्लब ने 2022-23 के बाद शुरुआती नौ मुकाबलों में इतने अंक हासिल नहीं किए थे। उस सत्र में भी आर्सेनल ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी। माइकल आर्टेटा के नेतृत्व में आर्सेनल ने उन लीग मुकाबलों में 81.1 प्रतिशत जीत दर्ज की है, जिनमें टीम ने पहले गोल किया। इस मामले में केवल सर एलेक्स फर्ग्यूसन, पेप गार्डियोला और जोस मोरिन्हो की टीमें उससे आगे रही हैं। आर्सेनल के काई हावर्ट्ज ने लिवरपूल के खिलाफ निर्णायक गोल करके प्रीमियर लीग में अपने कुल गोल की संख्या 46 पहुंचा दी। इसके साथ ही वह प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले जर्मन खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इल्काय गुंडोगन के 45 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हावर्ट्ज ने लिवरपूल के खिलाफ एनफील्ड में चेल्सी की ओर से अगस्त 2021 में भी गोल किया था, जिससे उनकी टीम ने 1-0 की बढ़त बनाई थी। ब्राइटन एंड होव एल्बियन ने एतिहाद स्टेडियम में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया। सिटी के खिलाफ 18वें प्रयास में ब्राइटन को पहली बार उसके घरेलू मैदान पर जीत मिली। मुकाबले में सिटी ने 21 शॉट लगाए, लेकिन एक भी गोल नहीं कर सकी। प्रीमियर लीग में 23 घरेलू मैचों के बाद यह पहला अवसर था, जब सिटी अपने मैदान पर गोल करने में नाकाम रही। ब्राइटन ने पिछले छह लीग मुकाबलों में से पांच में जीत दर्ज की है और इन सभी पांच जीत में उसने विपक्षी टीम को गोल नहीं करने दिया। इस सत्र में उसके नाम छह क्लीन शीट हैं, जो सभी टीमों में सर्वाधिक हैं। टोटेनहम हॉटस्पर ने क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी प्रीमियर लीग जीत दर्ज की। फरवरी, 2025 के बाद यह पहला मौका है, जब टोटेनहम ने लगातार तीन लीग मुकाबले जीते हैं। मैच में टोटेनहम ने 34 शॉट लगाए, जबकि पैलेस की टीम केवल दो शॉट लगा सकी। फरवरी 2016 के बाद किसी प्रीमियर लीग मुकाबले में टोटेनहम का यह सर्वाधिक शॉट लगाने का रिकॉर्ड है। सेंटर बैक खिलाड़ियों में पिछले सत्र की शुरुआत से अब तक केवल वर्जिल वान डाइक ने जान पॉल वान हेके से अधिक गोल किए हैं। वान डाइक के छह और वान हेके के पांच गोल हैं। चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हराया। इस मुकाबले में कोल पामर ने प्रीमियर लीग में चेल्सी के लिए अपना 50वां गोल पूरा किया। उन्होंने यह उपलब्धि 105वें मैच में हासिल की। चेल्सी के लिए उनसे कम मैचों में 50 गोल केवल जिमी फ्लॉयड हसलबैंक (84 मैच) और डिएगो कोस्टा (85 मैच) ने पूरे किए थे। दूसरी ओर, मैनचेस्टर यूनाइटेड का खराब प्रदर्शन जारी है। टीम सभी प्रतियोगिताओं में लगातार नौ मुकाबलों से जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इस दौरान उसे तीन ड्रॉ और छह हार मिली हैं। सितंबर 1984 के बाद यह पहला अवसर है, जब यूनाइटेड इतने लंबे समय तक जीत से दूर रही है। बोर्नमाउथ ने लीड्स यूनाइटेड को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी प्रीमियर लीग जीत दर्ज की। तीनों मुकाबलों में उसने विपक्षी टीम को गोल नहीं करने दिया। बोर्नमाउथ के एवेनिल्सन ने लगातार चार लीग मैचों में गोल किए हैं। यह प्रतियोगिता में उनका सबसे लंबा गोल करने का सिलसिला है। वह 2021 में राफिन्हा के बाद हैलोवीन के दिन प्रीमियर लीग में गोल करने वाले पहले ब्राजीलियाई खिलाड़ी भी बने।

न्यूजीलैंड ए को पहली पारी में मिली 78 रन की बढ़त, मुकेश कुमार ने झटके पांच विकेट

क्राइस्टचर्च। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज ने चार विकेट झटके। इसके बावजूद न्यूजीलैंड ए के निचले क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान की बदौलत मेजबान टीम पहली पारी में 424 रन बनाने में सफल रही और भारत ए पर 78 रन की बढ़त हासिल कर ली। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 32 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन क्रीज पर मौजूद थे। भारत ए अभी भी न्यूजीलैंड ए से 46 रन पीछे है। तीसरे दिन न्यूजीलैंड ए ने तीन विकेट पर 218 रन से आगे खेलना शुरू किया। पिछले दिन शतक लगाने वाले मैथ्यू बॉयल जल्दी आउट हो गए। इसके बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और मिचेल हे ने भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक सफलता से दूर रखा। दोनों ने एक घंटे से अधिक समय तक मोर्चा संभाले रखा। सिराज ने फॉक्सक्रॉफ्ट को 93 रन के निजी स्कोर पर पगबाधा आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। यह दिन का उनका दूसरा विकेट था। अगले ओवर में मिचेल हे विकेट के पीछे कैच दे बैठे, जबकि इसके कुछ ही देर बाद ब्रेट रैंडेल भी आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने से भारत ए ने मुकाबले में वापसी की और न्यूजीलैंड ए का स्कोर सात विकेट पर 291 रन हो गया। हालांकि, इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर चुनौती दी। न्यूजीलैंड ए के आखिरी तीन विकेटों ने 133 रन जोड़कर टीम का स्कोर 424 रन तक पहुंचा दिया। फ्रेजर शीट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। दसवें नंबर के बल्लेबाज जेडन लेनॉक्स और अंतिम बल्लेबाज जारोड मैके ने करीब 25 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना किया। इस साझेदारी को दूसरे ओवर में ही तोड़ने का मौका मिला था, लेकिन सिराज ने 12 रन पर खेल रहे लेनॉक्स का आसान कैच छोड़ दिया। भारतीय स्पिनरों को भी लगातार 45 ओवर की गेंदबाजी के बाद सफलता मिली। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी के 30वें ओवर में मैके को बोल्ड कर न्यूजीलैंड ए की पारी समेट दी। इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने दिन का बाकी खेल बिना किसी परेशानी के निकाल दिया।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का चैंपियन बना मैनपाट टाइटंस

रायपुर। मैनपाट टाइटंस ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के उद्घाटन संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 गोल से पराजित कर लीग की पहली चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मुकाबला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में खेला गया। अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के उद्घाटन संस्करण के फाइनल में आज मैनपाट टाइटंस ने संस्कारधानी टाइटंस को 4-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। छत्तीसगढ़ सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस लीग में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया था। मैनपाट टाइटन्स ने मैच की तेज शुरुआत की और शुरुआती मिनटों में कुछ मूव बनाए। उन्होंने शुरुआत में ही सर्कल में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया, जो किसी भी टीम के लिए हमेशा एक अच्छा संकेत होता है। लेकिन काउंटर पर शाहरुख ने एक मौका दिया, जहां उनके शॉट को डिफेंडर ने रोक दिया। मैनपाट टाइटन्स ने तीसरे क्वार्टर में रुख बदलने की कोशिश की, जब संदीप ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन उनकी बढ़त देर तक नहीं रही। स्ट्राइकर्स ने भी पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। अंतिम समय में मैनपाट ने बेहतर टीमवर्क से दो गोल और दागे तथा स्कोर 4-2 कर लीग का पहला चैंपियंन बनने में कामयाब रही। लीग में कुल 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि बांटी गई। विजेता टीम मैनपाट टाइटंस को 11 लाख रुपये और उप विजेता संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 6 लाख रुपये मिले। शाहरुख अली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आशीष तानी पूर्ति (13 गोल) को लीग का टॉप स्कोरर और हिमांशु को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। स्थानीय खिलाड़ी मोहित नायक ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। संदीप कुमार लीग के इमर्जिंग प्लेयर बने।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा से ज्यादा शतक लगा सकते हैं विराट कोहली: पुजारा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की तुलना में विराट कोहली के शतक लगाने की संभावना अधिक है। उन्होंने इसके पीछे दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की भूमिका और परिस्थितियों को वजह बताया। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिषेक नायर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो अलग-अलग वनडे टीमों के चयन और यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिलने पर अपनी राय रखी। दोनों ने ये बातें जियोहॉटस्टार के कार्यक्रम 'आउट ऑर नॉट आउट' में कहीं।



जियोहॉटस्टार के कार्यक्रम 'आउट ऑर नॉट आउट' में पुजारा ने कहा कि रोहित शर्मा की भूमिका पावरप्ले में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की होती है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनकी यह भूमिका बदल सकती है और वह शतक लगाने के लिए अधिक समय ले सकते हैं। हालांकि, विराट कोहली के पास शतक बनाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और उनकी भूमिका पारी को संभालने की होती है। उन्होंने कहा, 'विराट का खेल पारी को संभालने पर आधारित है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी के लिए वनडे प्रारूप में शतक बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी तय होती है, लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित की तुलना में विराट के शतक लगाने की संभावना अधिक है। अभिषेक नायर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम और मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने पिछली बार भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज जीती थी, जिससे भारतीय प्रशंसकों को निराशा हुई थी। ऐसे में आगामी टेस्ट सीरीज में भारत को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। नायर ने कहा, 'न्यूजीलैंड भारत आया था और उसने टेस्ट सीरीज में हमें हराया था। इससे मुझे भी तकलीफ हुई थी और बाकी प्रशंसकों को भी। यह बड़ी सीरीज है। विश्व कप महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी उसके लिए समय है। मेरे लिए यह टेस्ट सीरीज गौतम गंभीर और भारतीय प्रशंसकों के लिहाज से निर्णायक है। उन्होंने आगे कहा, 'मैं चाहता था कि केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, जो दोनों प्रारूपों में खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट पर ही ध्यान दें। क्योंकि अब उन्हें पहले वनडे की तैयारी करनी है और उसके बाद टेस्ट मैच खेलने हैं। मेरी राय में उन्हें एक-दो महीने लाल गेंद से अभ्यास करने का समय देना चाहिए था। जिस तरह न्यूजीलैंड ने भारत में हमें हराया, उसी तरह हमें वहां जाकर उसे हराना चाहिए।'

यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में शामिल नहीं किए जाने पर नायर ने कहा कि चयनकर्ताओं ने संभवत: उनसे इस बारे में बात की होगी। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पारी की शुरुआत करने के कारण जायसवाल को वनडे टीम में मौका नहीं मिला होगा। ऐसे में उन्हें टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहिए। नायर के अनुसार, जायसवाल को यह समझाया गया होगा कि वनडे टीम में जगह नहीं मिलने के दौरान वह रणजी ट्रॉफी खेलकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इससे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की जीत में योगदान देने का बेहतर अवसर मिलेगा। वनडे सीरीज के परिणाम को लेकर पुजारा ने 2-2 से बराबरी का अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि शुरुआती तीन मुकाबलों में भारतीय टीम का एक संयोजन खेलेगा, जबकि अंतिम दो मैचों में अलग टीम उतरेगी। ऐसे में न्यूजीलैंड को थोड़ा फायदा मिल सकता है। पुजारा ने कहा, 'मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा फायदा है, क्योंकि पांचों मैचों में भारत की एक जैसी टीम नहीं खेलेगी। हालांकि, शुरुआती तीन मैचों में मैं भारतीय टीम का समर्थन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगी। अंतिम दो मैच थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सीरीज में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20 टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका, महली बियर्डमैन और ओली पीक शामिल

सिडनी,एजेंसी। इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वनडे और टी20 टीमों की घोषणा कर दी है। युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन, प्रतिभाशाली बल्लेबाज ओली पीक और ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स तथा लियाम स्कॉट को वनडे टीम में जगह दी गई है। वहीं, निकिल चौधरी और जोएल डेविस को टी20 टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज लचलान शॉ और सैम हार्पर को पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज 13 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। घरेलू मैदान पर होने वाली इस सीरीज में आठ नए खिलाड़ियों को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने का अवसर मिल सकता है। बियर्डमैन, पीक, एडवर्ड्स, चौधरी, स्कॉट और डेविस इस साल सर्दियों के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दौरों पर सफेद गेंद के अंतरराष्ट्रीय मैचों में पदार्पण कर चुके हैं। हार्पर और शॉ अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं।

मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम में अनुभवी खिलाड़ियों का मुख्य समूह बरकरार रखा गया है। हालांकि, तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को आराम दिया गया है।



दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद टीम को दिसंबर से लगातार 10 टेस्ट मैच खेलने हैं।

केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में मिली हार के बाद ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस और कूपर कोनोली को वनडे टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, ये खिलाड़ी टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया को नौ दिसंबर से पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। न्यूजीलैंड मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर पिछले पांच में से तीन टेस्ट हारने के बाद वापसी की कोशिश करेगा। इसके बाद टीम भारत के दौरे पर पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलेगी। मार्च में मेलबर्न में टेस्ट क्रिकेट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष मुकाबला भी आयोजित होगा। महली बियर्डमैन ने पिछले साल जनवरी में लाहौर में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था, लेकिन सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले अभ्यास के दौरान उन्हें परेशानी हुई। जांच में उनकी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर का पता चला, जिसके कारण उनका पिछला सत्र प्रभावित हुआ। चोट से उबरने के बाद उन्होंने अक्टूबर में भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से सीमित ओवरों के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। पुडुचेरी में एक मैच में उन्होंने छह ओवर में 23 रन देकर चार विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा कि बियर्डमैन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में तीनों प्रारूपों का खिलाड़ी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र बाहर

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख खिलाड़ी मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों से उबर रहे हैं, लेकिन चार नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होने वाली वनडे सीरीज तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, चैपमैन को यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में खेलते समय बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। हाल ही में कराई गई एमआरआई जांच के बाद उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए दो सप्ताह और पुनर्वास की जरूरत है। वहीं, रचिन रवींद्र एक प्रचार कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान हुए हादसे में दाएं कंधे की हड्डी खिसकने के कारण चोटिल हो गए थे। उन्हें भी मैदान पर पूरी क्षमता से उतरने के लिए अभी और समय चाहिए। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि चैपमैन और रचिन टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। चैपमैन चोट से वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि रचिन का कंधा अभी सफेद गेंद के क्रिकेट में आराम से क्षेत्ररक्षण करने की स्थिति में नहीं पहुंचा है। इस महीने के आखिर में टेस्ट सीरीज भी होनी है, इसलिए टीम उनके मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट को पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। उन्हें पहले ही सीरीज के अंतिम दो मुकाबलों के लिए चुना गया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को भी शुरुआती तीन मैचों के लिए टीम में जगह मिली है, जबकि ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट अंतिम दो मुकाबलों के लिए टीम से जुड़ेंगे। तेज गेंदबाज मैट फिशर को भी शुरुआती तीन मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। उन्हें पहले केवल अंतिम दो वनडे के लिए चुना गया था। इस बीच, दाएं पैर की जांघ की मांसपेशी में हल्की चोट के कारण पिछले तीन टी20 मुकाबलों से बाहर रहे मैट हेनरी दो नवंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। हालांकि, उनकी उपलब्धता का फैसला फिटनेस आकलन के बाद किया जाएगा। भारत के खिलाफ पहले तीन वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर।

अंतिम दो वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग।

एक नजर

फ्रांस में सी-न्यूज को बंद करने की मांग, याचिका पर 5.53 लाख लोगों ने किए हस्ताक्षर

पेरिस,एजेंसी। फ्रांस के समाचार चैनल सी-न्यूज को बंद करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर साढ़े पांच लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समर्थन के बाद अब फ्रांस की नेशनल असेंबली में इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, बहस आयोजित करने का अंतिम फैसला संबंधित संसदीय आयोग की समीक्षा के बाद ही होगा। नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर उपलब्ध याचिका के मुताबिक, इसे 10 जून 2026 को शुरू किया गया था। सोमवार को 14:34 जीएमटी तक इस पर 5,53,474 हस्ताक्षर दर्ज किए जा चुके थे। याचिका में सी-न्यूज को फ्रांस के प्रसारण माध्यमों से हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि यह समाचार चैनल के बजाय 'प्रचार का माध्यम' बन गया है। कंजर्वेटिव अरबपति विन्सेंट बोलोरे के स्वामित्व वाला चैनल सी-न्यूज आव्रजन और अपराध जैसे मुद्दों पर अपने सख्त रुख के लिए जाना जाता है। चैनल के आलोचकों का आरोप है कि उसकी संपादकीय दिशा दक्षिणपंथी नेशनल रैली (आरएन) पार्टी की राजनीतिक लाइन के करीब होती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि चैनल की कवरेज से पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हालांकि, इन आरोपों पर चैनल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। फ्रांस की नेशनल असेंबली के नियमों के अनुसार, किसी याचिका पर पांच लाख हस्ताक्षर होने के बाद संसद में सार्वजनिक बहस आयोजित की जा सकती है। लेकिन इसके लिए पहले एक आयोग याचिका की समीक्षा करता है और तय करता है कि इस पर बहस कराई जाए या नहीं।

अटलांटिक महासागर में प्रवासी नौका हादसा, सात की मौत ; 380 से अधिक का रेस्क्यू

मैड्रिड। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास अटलांटिक महासागर में प्रवासियों की नाव हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि सोमवार को 380 से अधिक प्रवासियों को सुरक्षित बचाया गया। स्पेन की समुद्री बचाव सेवाओं ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, तटरक्षक बल ने सोमवार को लान्जारोटे द्वीप से करीब 150 किलोमीटर दूर एक नाव से 132 लोगों को बचाया। नाव पर दो लोगों के शव मिले। अधिकारियों ने बताया कि इसी यात्रा के दौरान पांच अन्य प्रवासियों की भी मौत हो गई थी और उनके शव समुद्र में फेंक दिए गए थे। इससे पहले, सोमवार को तटरक्षक नौकाओं ने लान्जारोटे और एल हिएरो द्वीप के पास से करीब 250 अन्य प्रवासियों को सुरक्षित निकाला। वहीं, रविवार को एल हिएरो के तट से 107 प्रवासियों को बचाया गया था। कैनरी द्वीप समूह के राष्ट्रपति फर्नांडो क्लाविहो ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर घटना पर दुख जताते हुए कहा कि अटलांटिक मार्ग एक बार फिर लोगों की जान ले रहा है। उन्होंने कहा कि हर मृतक के पीछे एक जिंदगी, एक कहानी और एक परिवार है।

'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स' में पाकिस्तान 130वें स्थान पर, न्याय व्यवस्था पर उठे सवाल

इस्लामाबाद। विश्व न्याय परियोजना (डब्ल्यूजेपी) के कानून के राज सूचकांक-2025 में पाकिस्तान को 143 देशों में 130वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग ने देश की न्याय व्यवस्था और संस्थागत ढांचे की स्थिति पर बहस तेज कर दी है। हालांकि, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि इस नतीजे को न तो खारिज किया जाना चाहिए और न ही इसके लिए बिना भेदभाव किसी एक संस्था को जिम्मेदार ठहराना उचित है। सूचकांक में सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा, नियामकीय प्रवर्तन, दीवानी न्याय और आपराधिक न्याय समेत आठ मानकों पर देशों का आकलन किया जाता है। पाकिस्तान दीवानी न्याय के मामले में 129वें और आपराधिक न्याय में 101वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार, दीवानी न्याय तक पहुंच और उसकी वहनीयता के मामले में पाकिस्तान का स्कोर 0.36, मुकदमों में अनुचित देरी के मामले में 0.28 और फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन में 0.35 रहा। लेखक शाहिद हुसैन कंबोयो के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय सूचकांक कमियों को सामने लाने और सुधारों को प्रोत्साहित करने का माध्यम हैं, लेकिन सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों के आकलन को संस्थागत रिकॉर्ड तथा आम लोगों के अनुभवों के साथ देखकर समझना चाहिए। उन्होंने लिखा कि रैंकिंग में सुधार का वास्तविक पैमाना केवल सूची में बेहतर स्थान हासिल करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों का कानून पर भरोसा मजबूत होना है।

पीएम बालेंद्र शाह की भारत यात्रा की तैयारियों के बीच बुधवार को नेपाल आएंगे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री

काठमांडू। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत यात्रा की तैयारियों के तहत बुधवार को दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नेपाल पहुंचेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भ्रमण के दौरान मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत राई के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी और आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नेपाल भ्रमण के दौरान मिस्री नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, विदेश मंत्री शिशिर खनाल सहित वरिष्ठ नेपाली अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात भी करेंगे। दौरा पूरा करने के बाद वह गुरुवार को नई दिल्ली लौट जाएंगे।

भारतीय सेना में गोरखा भर्ती फिर शुरू करने की मांग, काठमांडू में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन

काठमांडू। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती फिर से शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी संघ ने काठमांडू में और ऑल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी संघ ने काठमांडू के माइतीघर में प्रदर्शन किया। भारत सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बाद से गोरखा भर्ती बंद है। इससे पहले 12 अगस्त को पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों और युवाओं ने भर्ती फिर से शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी तरह, 19 अगस्त को भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के नेपाल दौरे के दौरान भी पूर्व गोरखा सैनिकों ने भर्ती फिर से शुरू करने के लिए पहल करने का आग्रह किया था। हालांकि, भारतीय सेना प्रमुख के नेपाल दौरे के दौरान भी भर्ती फिर से शुरू करने के मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बेरोजगार नेपाली युवाओं के लिए भरोसेमंद रोजगार की व्यवस्था करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सचिव स्तर के फैसले को खारिज करते हुए पूर्व गोरखा सैनिकों की संस्था या संगठन के पंजीकरण का नवीनीकरण करने की व्यवस्था करने की भी मांग की।

फ्लोरिडा में रिहायशी इलाके में बिजनेस जेट क्रैश, विमान में सवार सभी 9 लोगों की मौत

फ्लोरिडा,एजेंसी। अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा में रविवार को एक भीषण विमान हादसा हो गया। पाम बीच काउंटी के क्रेस्टहेवन इलाके में एक निजी बिजनेस जेट रिहायशी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। विमान घरों और कारों से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरा। हालांकि, जमीन पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया अल जजीरा तथा तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के हवाले से बताया कि, दुर्घटनाग्रस्त विमान लियरजेट 60 था। यह विमान टेक्सास के ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहामास के नॉर्थ एलेउथेरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। स्थानीय समयानुसार रविवार दोपहर करीब 12:50 बजे विमान क्रैश हो गया। अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घटना की पुष्टि करते हुए इसे भयावह त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) की जांच में सहयोग के लिए एफएए के कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाइवएटीसी.नेट पर उपलब्ध कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग में दुर्घटना से कुछ समय पहले पायलट को विमान पर बर्फ जमने की समस्या का जिक्र करते सुना गया। शुरुआत में पायलट ने स्थिति को संभालने योग्य बताया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने विमान के तेजी से ऊंचाई खोने की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद क्रू ने घबराते हुए कहा कि विमान जमीन से टकराने वाला है।



हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है और इसकी आधिकारिक जांच की जा रही है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने हादसे को विनाशकारी बताया है।

उन्होंने कहा कि विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ किसी मिसाइल जैसा दिखाई दे रहा था और सड़क के किनारे एक बड़ा गड्ढा बन गया। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में विमान के मलबे के आसपास आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दिया। दुर्घटना के बाद इलाके में आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया और सुरक्षा के मद्देनजर कई सड़कें बंद कर दी गईं। यह दुर्घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो एस्टेट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुई। पाम बीच काउंटी फायर रेस्क्यू ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की। वहीं, पाम बीच शेरिफ कार्यालय ने क्रेस्टहेवन बुलेवार्ड और 10वें एवेन्यू नॉर्थ के बीच मिलिट्री ट्रेल पर उत्तर और दक्षिण दिशा के रास्तों को बंद कर दिया। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) संयुक्त रूप से इस हादसे की जांच कर रहे हैं। जांच एजेंसियां विमान के तकनीकी रिकॉर्ड, कॉकपिट ऑडियो और दुर्घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की पड़ताल करेंगी। फिलहाल, अधिकारियों ने दुर्घटना के पीछे की वजह और विमान में सवार लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई से तालिबानी लड़ाके चौकियां छोड़कर भागे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दक्षिण वजीरिस्तान के अंगूर अड्डा इलाके में अफगान तालिबान की सीमा चौकियों से पाकिस्तानी ठिकानों पर कथित तौर पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। इसके जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए अफगान सीमा की कई चौकियों, मोर्टार ठिकानों और रक्षात्मक ढांचों को निशाना बनाया। दक्षिण वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के अनुसार, जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान के लड़ाके अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए।

पाकिस्तान की उर्दू टीवी चैनल दुनिया न्यूज और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिओ न्यूज के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अंगूर अड्डा क्षेत्र में अफगान सीमा चौकियों से पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों पर लगातार गोलीबारी की गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी के मुताबिक, इस गोलीबारी में पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह घटनाक्रम 27 अक्टूबर की रात अंगूर अड्डा इलाके में हुई गोलीबारी के कुछ दिनों बाद सामने आया है। पाकिस्तानी अधिकारियों और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, उस दौरान अफगान तालिबान की ओर से नागरिक घरों और अंगूर अड्डा बाजार को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई थी। इस दौरान एक रिहायशी इलाके में मोर्टार का गोला गिरने से एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। गोलाबारी में बाजार की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगान सीमा पर स्थित कई तालिबानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान में अफगान तालिबान की सात चौकियां नष्ट कर दी गई थीं। पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान शासन पर आरोप लगाता रहा है कि वह प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले करने से नहीं रोक रहा है।

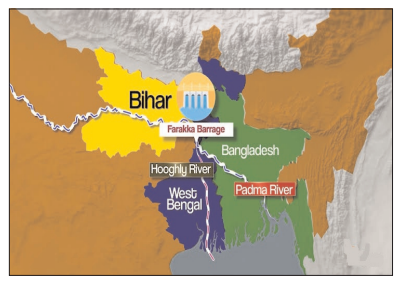
बुल्गारिया राष्ट्रपति चुनाव में इलियाना इओटोवा की शानदार जीत

सोफिया/मॉस्को। बुल्गारिया की कार्यवाहक राष्ट्रपति और बुल्गारिया सोशलिस्ट पार्टी (बीएसपी) की वरिष्ठ नेता इलियाना इओटोवा ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में जीत हासिल कर ली है। केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) ने सोमवार को 100 प्रतिशत चुनावी प्रोटोकॉल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक नतीजों की घोषणा की। इओटोवा को कुल 57.57 प्रतिशत वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी एवं कार्यवाहक प्रधानमंत्री आंद्रेई ग्यूरोव को 39.48 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती तथा तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू ने बताया कि चुनाव से पहले आए एग्जिट पोल में भी इओटोवा की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया गया था। पांच प्रमुख पोलिंग एजेंसियों के अनुमानों के मुताबिक उन्हें 56.6 से 58.2 प्रतिशत के बीच वोट मिलने की संभावना जताई गई थी। वहीं, ग्यूरोव को 38.6 से 40.6 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान था। चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझानों के बाद ग्यूरोव ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। सोफिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, 'हम नतीजों को स्वीकार करते हैं, चाहे वे कितने भी चौंकाने वाले क्यों न हों।' उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन देश के प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इओटोवा ने अपने चुनाव प्रचार में यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया था। उन्होंने यूक्रेन को और अधिक हथियार देने का विरोध किया और शांति वार्ता के जरिए संघर्ष समाप्त करने की वकालत की। पहले चरण के चुनाव में इओटोवा को 34.76 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि ग्यूरोव को 31.95 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। वहीं, दूसरे चरण में अपनी बढ़त को निर्णायक जीत में बदल दिया। इसके विपरीत ग्यूरोव ने यूरोपीय संघ और नाटो के साथ मजबूत सहयोग तथा यूक्रेन को समर्थन देने की नीति का समर्थन किया था। उन्होंने इओटोवा के रुख को लेकर सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताएं भी जताई थीं। इओटोवा तत्कालीन राष्ट्रपति रुमेन रादेव के समय उपराष्ट्रपति भी चुकी हैं। जनवरी में रादेव के इस्तीफे के बाद इओटोवा ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली थी। अप्रैल में हुए संसदीय चुनाव में रादेव के नेतृत्व वाली पार्टी 'प्रोग्रेसिव बुल्गारिया' ने 240 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 131 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। पार्टी ने इओटोवा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समर्थन किया था।

गंगा जल समझौते पर बांग्लादेश में सियासी गर्मी, भारत के ट्रांजिट पर रोक लगाने की मांग

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेश को गंगा के पानी में उसका उचित हिस्सा नहीं मिलता है, तो भारत को बांग्लादेश के रास्ते सामानों की आवाजाही और ट्रांजिट की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी पार्टी फरक्का तक एक बार फिर लंबा मार्च निकालने के लिए तैयार है। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को भी चेतावनी दी कि यदि उसने भेदभावपूर्ण रवैया जारी रखा, तो उसे भी अवामी लीग जैसी राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'द डेली स्टार' के अनुसार, नाहिद इस्लाम ने रविवार को ढाका के खमारबारी स्थित कृषिबिद इंस्टीट्यूशन बांग्लादेश में 'जातीय जुबो शक्ति' की ओर से आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों का आधार पानी का उचित बंटवारा और सीमा सुरक्षा होना चाहिए। नाहिद ने कहा, 'अगर बांग्लादेश को पानी नहीं मिलता है, तो भारतीय सामान भी बांग्लादेश में नहीं आ पाएंगे। कोई कॉरिडोर नहीं होगा और कोई ट्रांजिट नहीं होगा।' उन्होंने भारत को किसी भी तरह की गैरकानूनी कॉरिडोर या ट्रांजिट सुविधा देने का विरोध करते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गंगा जल



बंटवारा संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है। इसे देखते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा कि नए समझौते में बांग्लादेश के हिस्से के पानी की गारंटी के साथ नदी में नौवहन की सुविधा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी के ऐतिहासिक फरक्का मार्च का उल्लेख किया और कहा कि उनकी पार्टी भी जरूरत पड़ने पर फरक्का की ओर एक और लंबा मार्च आयोजित करेगी। देश की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करते हुए नाहिद इस्लाम ने संविधान सुधार परिषद का तत्काल गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फरवरी में हुए जनमत संग्रह के फैसले के अनुरूप जुलाई के नेशनल चार्टर को लागू किया जाना चाहिए। संविधान संशोधनों पर विचार के लिए सरकार की ओर से गठित संसदीय समिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। अब नए सिरे से विचार-विमर्श करने के बजाय फैसलों को लागू करने का समय है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, 'जनमत संग्रह के फैसले को लागू करें, वरना इस्तीफा दे दें। एनसीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीएनपी ने जुलाई के जन-विद्रोह को व्यापक राजनीतिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा सरकार भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती रही, तो उसे अवामी लीग जैसी राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नाहिद ने 18 महीनों में एक करोड़ नौकरियां देने के चुनावी वादे को लेकर भी सरकार की प्रगति पर सवाल उठाए। उन्होंने लोक सेवा आयोग (पीएससी) में नियुक्तियों के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए योग्यता के आधार पर भर्ती सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जुलाई का आंदोलन कोटा व्यवस्था के खिलाफ ही नहीं, बल्कि योग्यता और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने सरकार से युवा उद्यमियों को ऋण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी अपील की। कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की वेतन वृद्धि की मांग का समर्थन करते हुए नाहिद ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने पर जोर दिया। बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए 12,500 टका का न्यूनतम मासिक वेतन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश में किसी और मजदूर का खून बहे। इसके अलावा, नाहिद इस्लाम ने देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति और ईंधन की कीमतों को लेकर गृह मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई।

नेपाल में बालेंद्र शाह सरकार ने सीमा क्षेत्रों से जब्त किया 133 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध सामान



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सरकार ने सीमा पर निगरानी और सुरक्षा सख्त करने की नीति के अनुरूप मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शाह के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता संभालने के बाद से सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) ने 27 मार्च से 31 अक्टूबर तक सीमा क्षेत्रों से 133 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का अवैध सामान जब्त किया है।

इस अवधि में एपीएफ ने 17 अवैध हथियार जब्त किए और उनसे जुड़े मामलों में आठ लोगों को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 421 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से बड़ी मात्रा में गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन हेरोइन, नशीली गोलियां और इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली नशीली दवाएं जब्त की गईं। इस दौरान जब्त सामान का कुल मूल्य 133 करोड़ 26 लाख 91 हजार 599 रुपये रहा। एपीएफ ने मानव तस्करी और अवैध रूप से लोगों को सीमा पार ले जाने के जोखिम का सामना कर रहे 167 लोगों को भी बचाया। इनमें 118 बच्चे शामिल थे। इन मामलों में कथित रूप से शामिल 91 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा अतिक्रमण रोकने के लिए एपीएफ ने सीमा के दोनों ओर स्थित दसगजा क्षेत्र के 35 स्थानों से 237 संरचनाएं हटाईं। इसके अलावा 17 स्थानों पर 7.448 बीघा जमीन से फसलों को हटाया गया। बल ने 204 स्थानों पर सीमा क्षेत्र के 94.588 किलोमीटर हिस्से की सफाई भी की। एपीएफ के अनुसार इस अवधि में सीमा क्षेत्र के समुदायों के साथ संबंध मजबूत करने और जनजागरूकता बढ़ाने के लिए 2,806 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त बल के 141 सहायता डेस्कों से 3,49,908 लोगों और 13 पर्यटक सहायता डेस्कों से 10,654 लोगों को लाभ मिला।

उत्तर कोरिया ने क्लस्टर बम का किया परीक्षण, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों में तैनात करने की तैयारी

सियोल। उत्तर कोरिया ने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले क्लस्टर बम वॉरहेड का परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने रविवार को इसकी जानकारी दी। साथ ही प्योंगयांग ने इस साल के अंत तक विभिन्न प्रकार के क्लस्टर वॉरहेड अपनी सैन्य इकाइयों में तैनात करने की योजना जताई है।

दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रशासन ने शनिवार को यह परीक्षण किया। इसका उद्देश्य टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले क्लस्टर बम वॉरहेड की युद्धक क्षमता और प्रभाव का आकलन करना था। मिसाइल प्रशासन के अधीन शोध संस्थानों ने परीक्षण के बाद पुष्टि की कि 'स्टैंडर्ड टाइप-2' क्लस्टर बम वॉरहेड 12 से 13 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र में व्यापक विनाश करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रशासन के महानिदेशक ने बताया कि क्लस्टर बम वॉरहेड को उनके उपयोग और उद्देश्यों के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल के भीतर सैन्य इकाइयों को इस तरह सक्षम बनाया जाएगा कि वे अपने अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग प्रकार के वॉरहेड का चयन और इस्तेमाल कर सकें। उल्लेखनीय है कि क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं, जिनमें से दर्जनों से लेकर सैकड़ों छोटे विस्फोटक निकलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और अलग-अलग स्थानों पर विस्फोट करते हैं। इनके इस्तेमाल से आम नागरिकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होता है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उसने उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण गतिविधियों पर नजर रखी थी। सेना के अनुसार, मिसाइल उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में चोंगजू के आसपास से पीले सागर की दिशा में दागी गई। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने रविवार को कहा कि अमेरिका के साथ करीबी सूचनाओं के आदान-प्रदान के तहत मिसाइल प्रक्षेपण से पहले ही संबंधित गतिविधियों का पता लगा लिया गया था और सेना पूरी तरह सतर्क थी। सियोल स्थित कोरिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के महासचिव शिन जोंग-वू ने अनुमान जताया कि परीक्षण में इस्तेमाल की गई मिसाइल 'हवासोंग-11 रा' हो सकती है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने अप्रैल में भी इसी तरह की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड का परीक्षण करने का दावा किया था। उस समय उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और उनकी बेटी जू-ए ने परीक्षण की निगरानी की थी। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है, जब अटलांटा में हुई त्रिपक्षीय बैठक में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिकों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग दोहराई है। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि, इसके लिए प्योंगयांग को उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहमत होना होगा, जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। फिलहाल, दोनों नेताओं के बीच संभावित बैठक का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

एक नजर

कैट ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा, प्रदर्शन स्थल शहर से बाहर किया जाए

नई दिल्ली,एजेंसी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक आयोजनों के लिए शहर के बाहरी इलाकों में अलग से नियत स्थल अधिसूचित करने की मांग की है। कारोबार संगठन का कहना है कि दिल्ली में औसतन प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपये का व्यापार होता है। पिछले एक महीने में लगभग 14 दिन दिल्ली का सामान्य व्यापार प्रभावित हुआ है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापारिक एवं वितरण केंद्र है, जहां प्रतिदिन देश के विभिन्न राज्यों से लाखों व्यापारी खरीदारी करने और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आते हैं। पिछले एक महीने से अधिक समय से बने अशांत माहौल, धरने-प्रदर्शनों और यातायात संबंधी व्यवधानों के कारण बड़ी संख्या में व्यापारी दिल्ली नहीं पहुंच सके। इसका सीधा असर थोक बाजारों, खुदरा व्यापार, छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, परिवहन, होटल एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा है।

कैट कहा कि व्यापारियों ने अपने कारोबार में हुए इस भारी नुकसान को स्वयं झेला है, लेकिन उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से लिया है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर लाखों व्यापारियों के कारोबार, उनकी आजीविका और उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त व्यापार करने और आजीविका अर्जित करने के अधिकारों का इस प्रकार बाधित होना गंभीर चिंता का विषय है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि दिल्ली के व्यापारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद दिल्ली के व्यापारिक संगठनों एवं प्रमुख व्यापारिक नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष त्योहारी सीजन में दिल्ली के व्यापारियों को बिना किसी बाधा, भय अथवा यातायात व्यवधान के अपना कारोबार करने का अवसर मिलेगा और बाजारों में सामान्य व्यापारिक गतिविधियां पूरी स्वतंत्रता के साथ संचालित हो सकेंगी। कैट ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से आग्रह किया है कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में विरोध-प्रदर्शनों के लिए कुछ निर्धारित स्थानों को शीघ्र अधिसूचित किया जाए, ताकि भविष्य में राजनीतिक धरने, रैलियां एवं प्रदर्शन दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों, बाजारों और आम नागरिकों की आवाजाही को प्रभावित न करें। इससे विरोध-प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार की भी रक्षा होगी और दिल्ली के व्यापार तथा आम जनता की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां भी निर्बाध रूप से चलती रहेंगी।

हवाई अड्डों के शुल्क और कर कम होने से भारतीय बाजार में विमानन क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा : विली वॉल्श

नई दिल्ली,एजेंसी। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विली वॉल्श ने सोमवार को कहा कि भारत में एयरपोर्ट शुल्क बहुत अधिक हैं, इन्हें कम करने के साथ-साथ करों में कटौती से विमानन क्षेत्र को विस्तार का मौका मिलेगा। वॉल्श ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को अपनी लागत पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिल सकें। नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत में विमानन क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी लागत कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस कंपनियां एयरपोर्ट से बेहतर सुविधाएं और कम कीमत पर सेवाएं देने की उम्मीद करती हैं। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में कई एयरपोर्ट का प्रभावी रूप से एकाधिकार है, ऐसे में उनकी कीमतों पर ध्यान देना जरूरी है। अगस्त में सीईओ का पदभार संभालने के बाद वॉल्श ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखी और कहा कि विमानन कंपनी को 2028 की दूसरी तिमाही से चौड़े आकार वाले ए350 विमान मिलने शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की उड़ानों के बाजार में सफल होने के लिए इंडिगो के पास सभी आवश्यक खूबियां हैं। विली वॉल्श ने कहा कि ए350 विमानों में तीन श्रेणियों वाली सीट व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि इसमें बिजनेस श्रेणी में पूरी तरह 'बेड' बन जाने वालीं 16 सीट के साथ प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी श्रेणी की सीट होंगी। कंपनी को कई अवसर दिख रहे हैं और वह विमानन उद्योग की चुनौतियों से निपटेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विमानन कंपनी का ध्यान लागत आधार को बेहतर बनाए रखने पर है।

जामिया ने 'रन फॉर यूनिटी' में उत्साहपूर्ण भागीदारी और शपथ ग्रहण समारोह के साथ मनाई सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती

एम.जबिउल्लाह, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। 'राष्ट्रीय एकता दिवस-2026' के अवसर पर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के खेल-कूद एवं क्रीड़ा विभाग ने 31 अक्टूबर, 2026 को सरदार वल्लभभाई पटेल (भारत के लौह पुरुष) की 151वीं जयंती मनाने के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह और 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया।

जेएमआई के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ़ ने शपथ दिलाई और सुबह 9:00 बजे 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कुलपति की धर्मपत्नी, जेएमआई की छात्र कल्याण डीन प्रो. नीलोफर अफजल और खेल-कूद एवं क्रीड़ा विभाग के निदेशक प्रो. नफीस अहमद भी नवाब मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। इस कार्यक्रम ने जामिया बिरादरी को एकजुटता और राष्ट्रीय अखंडता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में जेएमआई की छात्र कल्याण डीन प्रो. नीलोफर अफजल, विधि संकाय के डीन प्रो. गुलाम यज़दानी, दंत चिकित्सा संकाय के डीन प्रो. नदीम यूनुस, ललित कला संकाय के डीन प्रो. शाह अबुल फैज़, मुख्य प्रॉक्टर प्रो. मो. असद मलिक, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के निदेशक डॉ. रिहान खान सूरी, फारसी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मोहसिन अली के साथ-साथ संकाय सदस्य, गैर-शिक्षण कर्मचारी, छात्र और स्थानीय समुदाय के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति और संस्थागत एकजुटता की सामूहिक भावना देखने को मिली। भारत के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल का दृष्टिकोण इस अटूट विश्वास पर टिका



था कि किसी राष्ट्र की असली ताकत उसकी पूर्ण एकता और अखंडता में निहित है। 562 से अधिक रियासतों को एक साथ जोड़कर, 'भारत के लौह पुरुष' ने एक ऐसा मजबूत और एकजुट गणतंत्र बनाया, जो क्षेत्रीय, भाषाई और सांप्रदायिक विभाजनों से ऊपर था। उनकी विरासत हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि आंतरिक सुरक्षा, सामूहिक राष्ट्रीय पहचान और आपसी सद्भाव ही राष्ट्र-निर्माण की मुख्य नींव हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के कुलपति, प्रो. मजहर आसिफ़ ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने न केवल एक राष्ट्र का नक्शा तैयार किया, बल्कि उसकी विविध आत्मा को एक एकल पहचान में पिरो दिया। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में, जामिया मिलिया इस्लामिया की यह जिम्मेदारी है कि वह इस मशाल को आगे ले जाए। यह 'रन फॉर यूनिटी' आज फिनिश लाइन पर खत्म नहीं होनी चाहिए—इसे समावेशिता, बौद्धिक विकास और राष्ट्र-निर्माण की दिशा में एक निरंतर चलने वाली यात्रा बनना चाहिए। हमारे छात्र कल के भारत के निर्माता हैं, और आज उनका संकल्प यह साबित करता है कि हमारी एकता अटूट है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार, प्रो. मो. महताब आलम रिज़वी ने 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते हम सब राष्ट्र के प्रति एक साझा संकल्प से जुड़े हों। आज, जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिवार एक साथ आगे बढ़ रहा है, तो हम एकजुटता, संस्थागत अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हमारे टीचिंग स्टाफ, नॉन-टीचिंग स्टाफ और छात्रों की भारी भागीदारी उस सौहार्दपूर्ण भावना को दर्शाती है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पहचान है। आइए, हम हर दिन एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें और एक समावेशी, प्रगतिशील और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान दें। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के खेल निदेशक, प्रो. नफीस अहमद ने कहा कि खेलों में लोगों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है, और आज मैदान पर दिख रही ऊर्जा हमारे राष्ट्र की सामूहिक ताकत को बखूबी दर्शाती है। एक साथ दौड़ने का अर्थ यह है कि भले ही हमारे रास्ते अलग-अलग हों, लेकिन हमारी मंजिल एक मजबूत, स्वस्थ और एकजुट भारत है। सच्ची फिटनेस केवल शारीरिक नहीं होती; यह हमारे सामूहिक संकल्प की मजबूती है कि हम एकजुट रहें, अनुशासित रहें और देश की प्रगति के प्रति समर्पित रहें।'

स्टॉक मार्केट में ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स की सांकेतिक बढ़त के साथ एंट्री, मामूली मुनाफे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली। रियल एसेट्स और प्राइवेट क्रेडिट मार्केट्स पर केंद्रित अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में फंड मैनेज करने और वैश्विक व घरेलू संस्थागत निवेशकों, एचएनआई और फैमिली ऑफिसों को इनवेस्टमेंट सॉल्यूशन देने वाली कंपनी ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड के शेयर आज स्टॉक मार्केट में मामूली बढ़त के साथ लिस्ट हुए। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 1,665 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 0.487 प्रतिशत के सांकेतिक प्रीमियम के साथ 1,673 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 0.63 प्रतिशत के मामूली प्रीमियम के साथ 1,675.50 रुपये के स्तर पर हुई। लगभग सपाट स्तर पर हुई लिस्टिंग के बाद इस शेयर की चाल में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा। बिकवाली के दबाव में ये शेयर गिर कर 1,600.10 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। वहीं बाद में लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 1,762.55 रुपये के स्तर तक आ गया। बाजार में दिन भर हुई खरीद बिक्री के बाद ये शेयर 1,727.05 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इस तरह पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 62.05 रुपये यानी 3.73 प्रतिशत का फायदा हो गया।

कंपनी का 1,200 करोड़ रुपये का आईपीओ 26 से 28 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 5.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 13.80 गुना (एक्स एंकर) सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 4.81 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन सिर्फ 1.08 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 5 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 72,07,207 शेयर जारी किए गए हैं। यह पूरा इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पर आधारित था, यानी इसके तहत कोई भी फ्रेश शेयर जारी नहीं किया गया है। आईपीओ के जरिये जुटाई गई पूरी रकम बेचने वाले प्रमोटर और शेयरहोल्डर एडेलवाइस सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास गई है। कंपनी को उम्मीद है कि इस लिस्टिंग से उसकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी और शेयरों को एक पब्लिक मार्केट मिलेगा। ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी की वित्तीय सेहत में पिछले वित्त वर्षों के दौरान शानदार सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 229.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ

दीपोत्सव में श्रद्धालुओं को न हो परेशानी, व्यवस्थाएं समय से पूरी करें अधिकारी : योगी आदित्यनाथ

अयोध्या,एजेंसी। दीपोत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित पीएफसी सभागार में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली और निर्देश दिया कि दिव्य दीपोत्सव को भव्यता के साथ संपन्न कराने में कोई कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अयोध्या आने वाले किसी भी श्रद्धालु, अतिथि या पर्यटक को असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समय से तैयारियां पूरी करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से दीपोत्सव की तैयारियों की प्रगति पूछी। उन्होंने वीवीआईपी अतिथियों, साधु-संतों और विशिष्ट जनों के आगमन पर उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा। साथ ही देश-विदेश से दर्शन-पूजन और पर्यटन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं तथा अन्य आगंतुकों के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए और किसी भी स्तर पर अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनने दी जाए।

मुख्यमंत्री ने आयोजन के दौरान पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा सहित सभी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों, घाटों और आयोजन स्थलों पर स्वच्छता की निरंतर व्यवस्था रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और आवागमन के प्रबंध प्रभावी बनाए जाएं। संबंधित विभाग अपने दायित्वों का समयबद्ध ढंग से निर्वहन करें और तैयारियों की लगातार निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव को जनभागीदारी का उत्सव बनाने पर



भी जोर दिया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाकर आयोजन में सहभागिता करें। सभी शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य संस्थान भी अपने परिसरों में दीप प्रज्ज्वलित करें, जिससे पूरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव की भव्यता केवल आयोजन स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें पूरे जनपद की भागीदारी दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर तैयारियों की निगरानी करें। जहां भी कोई कमी दिखाई दे, उसे तत्काल दूर कराएं और सभी व्यवस्थाएं समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करें। बैठक में जनप्रतिनिधियों, मंडलायुक्त सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पटेल ने 8,169 नवनियुक्त विद्यासहायकों को सौंपे नियुक्ति अनुशंसा पत्र

गांधीनगर,एजेंसी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त विद्यासहायकों को अमृतकाल के ऐसे प्रहरी बताया, जिनके कंधों पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा से जुड़ रहे शिक्षक विद्यार्थियों का मजबूत शैक्षणिक और नैतिक निर्माण करें, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सकें। अडालज स्थित त्रिमंदिर में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित नवनियुक्त विद्यासहायकों के अभिनंदन और अनुशंसा पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8,169 नवनियुक्त विद्यासहायकों को अनुशंसा पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री रिवाबा जाडेजा भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8,000 से अधिक विद्यासहायकों की भर्ती में 6,000 से अधिक महिला उम्मीदवारों का चयन होना शिक्षा क्षेत्र में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में शुरू किए गए कन्या केलवणी महोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव का अभियान आज वटवृक्ष बन चुका है और उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। उम्मीदवारों को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। इस उपलब्धि पर अभिभावकों और परिवारजनों में खुशी और



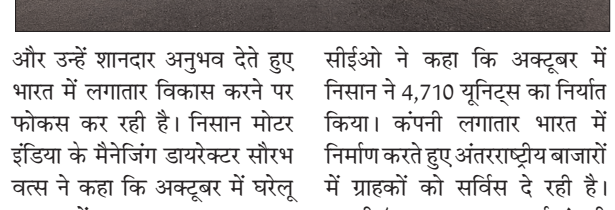
गर्व का माहौल है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि शिक्षा विभाग आगामी समय में लगभग 10,000 और शिक्षकों की भर्ती की योजना बना रहा है।

शिक्षक के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत सम्माननीय है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक क्यों न बन जाए, वह अपने शिक्षक के सामने हमेशा नतमस्तक होता है। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण देते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक का व्यवहार और आचरण बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 12,000 विद्यासहायकों की ऐतिहासिक भर्ती पूरी की है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक गुजराती माध्यम की लगभग 11,000 और अन्य माध्यमों की लगभग 987 रिक्तियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया योग्यता और तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, कौशल विकास और अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। बच्चों को रटने के बजाय समझ के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहानियों, गतिविधियों, प्रयोगों और तकनीक के माध्यम से कक्षाओं को अधिक रोचक और जीवंत बनाने का आह्वान किया। शिक्षा राज्य मंत्री रिवाबा जाडेजा ने कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता होते हैं। राष्ट्र का भविष्य कक्षाओं में ही तैयार होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, मूल्य, कौशल और चरित्र का निर्माण करना भी है। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से बच्चों के भीतर ज्ञान और संस्कारों का विकास कर राज्य तथा देश का नाम रोशन करने की अपील की।

निसान मोटर इंडिया ने अक्टूबर में घरेलू बाजार में कुल 3,600 वाहनों की थोक बिक्री दर्ज की

नई दिल्ली। वाहन विनिर्माता कंपनी निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईपीएल) ने अक्टूबर माह में घरेलू बाजार में कुल 3,600 वाहनों की थोक बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में बिकीं 2,402 इकाई के मुकाबले 50 फीसदी की वृद्धि है। निसान के लिए यह लगातार आठवां महीना रहा, जब कंपनी की घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

निसान मोटर इंडिया ने सोमवार को अपनी अक्टूबर की बिक्री रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि जनवरी से अक्टूबर के बीच निसान ने घरेलू और विदेशी बाजारों को मिलाकर कुल 85,124 गाड़ियों की थोक बिक्री की है। कंपनी ने बताया कि घरेलू होलसेल बिक्री में सालाना आधार पर 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने बताया कि यह प्रदर्शन निसान के लगातार बढ़ते पोर्टफोलियो को प्रति ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया को दिखाता है। इसके पोर्टफोलियो में नई निसान टेक्टॉन, मैग्नाइट और ग्रेवाइट है। साथ ही बढ़ते डीलर नेटवर्क से भी कंपनी के शानदार प्रदर्शन में योगदान मिला है। कंपनी व्यापक प्रोडक्ट ऑफरिंग, ग्राहकों तक ज्यादा पहुंच



और उन्हें शानदार अनुभव देते हुए भारत में लगातार विकास करने पर फोकस कर रही है। निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने कहा कि अक्टूबर में घरेलू बाजार में सालाना आधार पर 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज करना निसान ब्रांड में ग्राहकों के लगातार बढ़ते भरोसे और भारत में हमारी प्रगति को दिखाने वाली है। उन्होंने कहा कि जनवरी से अक्टूबर के बीच घरेलू एवं निर्यात बाजारों में 85,124 यूनिट्स की बिक्री के साथ हम लगातार अपने पोर्टफोलियो और डीलर नेटवर्क को मजबूत बना रहे हैं। सौरभ वत्स ने कहा कि धनतेरस और दीवाली आने वाली है और हम अपने खास प्रोडक्ट्स एवं बेहतरीन अनुभव के साथ अपने ग्राहकों को सर्विस देने पर फोकस करते रहेंगे। निशान सीईओ ने कहा कि अक्टूबर में निसान ने 4,710 यूनिट्स का निर्यात किया। कंपनी लगातार भारत में निर्माण करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ग्राहकों को सर्विस दे रही है। अपनी 'वन कार, वन वर्ल्ड' की रणनीति के तहत निसान भारत एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ग्राहकों को ऐसे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रही है, जिन्हें गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह निसान के वैश्विक परिचालन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि निसान के एसयूवी डीएनए पर डिजाइन की गई नई निसान टेक्टॉन में जापान की रिफाइंड क्राफ्टमैनशिप, इंटेलीजेंट टेक्नोलॉजी, कमांडिंग परफॉर्मेंस और हर दिन की व्यावहारिकता को साथ लाया गया है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)